

दिल्ली के उच्च न्यायालय नई दिल्ली

सुरक्षित : 12 मई 2023
उद्घोषित: 15 मई 2023

सि.वा. (वाणि.) 101/2022

अस्ट्राज़ेनका ऐ बी और अन्य

..... वादी

द्वारा : श्री प्रवीण आनंद, सुश्री वैशाली मित्तल और
श्री सिद्धांत चमोला, अधिवक्ता

बनाम

वेस्टकोस्ट फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड

.... प्रतिवादी

द्वारा : श्री विकास खेरा और श्री वेद प्रकाश,
अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सी. हरि शंकर

निर्णय

15.05.2023

अं.आ 21995/2022 (सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के अधीन)

1. यह प्रतिवादी वेस्टकोस्ट फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन है, जिसमें वादी एस्ट्राज़ेनेका ए. बी. द्वारा स्थापित सी.एस. (सी.ओ.एम.एम.) 101/2022 की अस्वीकृति की मांग की गई है।

2. मैंने प्रतिवादी-आवेदक के विद्वान वकील श्री विकास खेड़ा और वादी-गैर-आवेदक के विद्वान वकील श्री प्रवीण आनंद को विस्तार से सुना है।

3. श्री खेरा इस आवेदन में तीन आधारों पर अपने मामले की भविष्यवाणी करते हैं।

(1) आर्थिक अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता

4. श्री खेरा सबसे पहले तर्क देते हैं कि मुकदमा आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण गलत है, क्योंकि इसे जिला न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है। श्री खेरा प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमा एक समयबद्ध कार्रवाई की प्रकृति का है, जो केवल इस आशंका पर आधारित है कि प्रतिवादी कथित मुकदमा से उल्लंघन करने वाले उत्पाद को बाजार में लॉन्च करेगा। टोनी एंड गाय में इस न्यायालय की एक समन्वित एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए **प्रोडक्ट्स लिमिटेड वी. श्याम सुंदर नागपाल 1, श्री खेरा प्रस्तुत करते हैं कि ए** हर्जाने के लिए मुकदमा एक समयबद्ध मुकदमे में बनाए रखने योग्य नहीं है, जो केवल आशंका पर आधारित है। चूंकि, वर्तमान वाद में, इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के आह्वान को अभियोक्ता द्वारा पूरी तरह से मुकदमे में मुकदमा किए गए ₹1,000/- के नुकसान के आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई है, श्री खेड़ा प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि वर्तमान जैसे मुकदमे में कोई नुकसान नहीं मांगा जा सकता है, इसलिए मुकदमा जिला न्यायालय के समक्ष दायर करना होगा क्योंकि यदि नुकसान के दावे को बाहर रखा जाता है, तो मुकदमे का मूल्य केवल ₹1,000/- होगा।

5. आपत्ति सारहीन है। टोनी एंड गाय 1, पैरा 11 में, स्पष्ट रूप से नोट करता है कि, उस मामले में, -स्वीकार्य रूप से प्रतिवादी ने उपयोग नहीं किया है चिह्न और ट्रेडमार्क में वादी के स्वामित्व अधिकारों पर या तो उसी का उल्लंघन करके या पारित करके आक्रमण नहीं किया है। के रूप में इसके विरुद्ध, वर्तमान मामले में, एक विशिष्ट आरोप

है कि प्रतिवादी ने बाजार में उल्लंघन करने वाले उत्पादों का निर्माण शुरू कर दिया है और पहले से ही बेच रहा है, या बिक्री शुरू करने की प्रक्रिया में है। इसे और टालने की आवश्यकता नहीं है, और न ही इसे देखने की आवश्यकता है। आदेश VII नियम 11 वाद में किए गए दावों पर आधारित है, जो दोषारोपण करने वाले पर लिया जाना है। सही है। इस प्रकार, वर्तमान मामले की तुलना टोनी एंड गाय 1 से नहीं की जा सकती है। यह सादृश्य स्पष्ट रूप से गुमराह करने वाला है।

6. इस मुकदमा, आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अभाव में आदेश VII नियम 11 के तहत वर्तमान मुकदमे को खारिज करने का कोई मामला मौजूद नहीं है।

(II) क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता

7. श्री खेरा अगला आरोप लगाते हैं कि मुकदमा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण गलत है, क्योंकि प्रतिअभियोक्ता दिल्ली के बाहर स्थित है और अभियोक्ता 1 स्वीडन में है। हालाँकि अभियोक्ता 1 का दिल्ली में एक अधीनस्थ कार्यालय, अभियोक्ता 2 है, श्री खेड़ा ने अपनी चुनौती को पूरी तरह से सी. पी. सी. की खंड 20 पर व्यक्त किया है।

8. सबसे पहले, एक प्रतिवादी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर मुकदमे की बर्खास्तगी या अस्वीकृति की मांग नहीं मुकदमा सकता है। ऐसे मामले में आदेश VII नियम 10 लागू होगा और न ही आदेश VII नियम 11, और न्यायालय को केवल उचित मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के मुकदमा मुकदमा वापस करने के मुकदमा कहा जा सकता है।

9. मैं यहाँ यह ध्यान दें कर सकता हूँ कि श्री खेड़ा ने भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के पहलू पर कोई तर्क नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप श्री आनंद की ओर से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

10. आवेदन में प्रार्थना शिकायत की अस्वीकृति के लिए है। इस तरह की प्रार्थना क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी विशेष रूप से आदेश VII नियम 10 द्वारा कवर की गई है। इसलिए, मैं उक्त प्रार्थना पर किसी भी निष्कर्ष को वापस करने का प्रस्ताव नहीं करता।

11. यदि प्रतिवादी ऐसा चुनता है, तो सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 10 के तहत एक अलग आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है। यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो यह अपने गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा। मैंने इस मुद्दे पर अपना दिमाग नहीं लगाया है, क्योंकि श्री खेरा ने भी कभी इस पर बहस नहीं की थी, और इसलिए, किसी भी तरह से उस पर किसी भी निष्कर्ष को वापस नहीं करते हैं।

(III) द अलॉयज वोबेन विवाद

12. दूसरा आधार जिस पर श्री खेड़ा वर्तमान मुकदमे को खारिज मुकदमाने की मांग मुकदमाते हैं, वह उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैरा 19 पर आधारित है। **एलॉयस वोबेन बनाम योगेश मेहरा 2 में, जो इस प्रकार है:**

19. यदि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा कोई कार्यवाही शुरू की गई है, तो यह उसी व्यक्ति के पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत रद्द याचिका दायर करने के अधिकार को ग्रहण करेगा। और साथ ही, पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत दिए गए अधिकार का आह्वान करने के लिए, एक-प्रतिवाद दायर करने के लिए (एक-उल्लंघन मुकदमे के जवाब में-एक पेटेंट के निरसन की मांग करने के लिए)। यह, हमारे विचार में, पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) की शुरुआत में दिखाई देने वाले इन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन शब्दों का स्वाभाविक प्रभाव होगा। और यदि उपरोक्त अर्थ इन शब्दों को नहीं दिया जाता है-इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, तो वे अनावश्यक और अनावश्यक होंगे। हालाँकि ऊपर उल्लिखित स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त स्थिति, हमारे विचार में, कभी भी उत्पन्न होने की

संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, पेटेंट अधिनियम की खंड 25, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। प्रक्रिया आवेदन दाखिल करने के साथ शुरू होती है। दूसरा चरण मांगे गए पेटेंट के विवरण के प्रकाशन पर विचार करता है। अगले चरण में विरोध (पेटेंट के अनुदान के लिए) के माध्यम से अभ्यावेदन दाखिल करने की परिकल्पना की गई है। यह नियंत्रक द्वारा पेटेंट देने या अस्वीकार करने के दृढ़ संकल्प में आगे बढ़ता है। नियंत्रक के निर्णय से अनुदान (पेटेंट) का प्रकाशन होता है। यह प्रक्रिया पेटेंट के अनुदान के निर्णय को अंतिम रूप देती है। वैसे भी, यह अंत में नहीं है पेटेंट धारक के अधिकार को स्पष्ट करें। अनुदान मिलने के बाद प्रकाशित, -कोई भी इच्छुक व्यक्ति, अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर विरोध का नोटिस जारी कर सकता है। एक पेटेंट। यदि और जब, पेटेंट के अनुदान के लिए उठाई गई चुनौतियों का पेटेंट धारक के लाभ के लिए अनुकूल रूप से निपटारा किया जाता है, तो पेटेंट रखने का अधिकार तब और फिर ही कहा जा सकता है क्रिस्टलीकृत हो गए हैं। इसी तरह, यदि पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर विरोध की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो अनुदान को स्पष्ट माना जाएगा। अतः केवल पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत विचार की गई प्रक्रिया की परिणति पेटेंट को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है। इसलिए, यह असंभव और काफी असंभव है कि जब तक खंड 25 (2) के तहत कार्यवाही लंबित है, या पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर एक "उल्लंघन मुकदमा" दायर किया जाएगा।।

(जोर दिया गया)

श्री खेड़ा प्रस्तुत करते हैं कि, वर्तमान मामले में, यौगिक ओसिमार्टिनिब का मुकदमा करने वाला मुकदमा पेटेंट आई. एन. 297581 (आई. एन. '581), 11 जून 2018 को अभियोक्ता को दिया गया था, जिसके बाद, पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत सनशाइन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (-सनशाइन) द्वारा 14 मई 2019 को और नैटको फार्मा लिमिटेड (-नैटको) द्वारा 10 जून 2019 को क्रमशः पोस्ट ग्रांट विरोध दायर किए गए थे। वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था

3 (2) पेटेंट के अनुदान के बाद किसी भी समय, लेकिन पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, कोई भी इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निर्धारित तरीके से नियंत्रक को विरोध की सूचना दे सकता है, अर्थात्:—

(क) कि पेटेंटी या वह व्यक्ति जिसके तहत या जिसद्वारा से वह दावा करता है, ने गलत तरीके से आविष्कार या उसका कोई हिस्सा उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है जिसके तहत या जिसद्वारा से वह दावा करता है;

(ख) कि आविष्कार जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है -

(i) 1 जनवरी, 1912 को या उसके बाद भारत में किए गए पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी भी विनिर्देश में; या

((ii) भारत में या कहीं और, किसी अन्य दस्तावेज़ में:

बशर्ते कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान नहीं बनाता है।

(ग) जहां तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार का दावा पेटेंटी के दावे की प्राथमिकता तिथि को या उसके बाद प्रकाशित पूर्ण विनिर्देशन के दावे में किया गया है और भारत में पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किया गया है, जो एक ऐसा दावा है जिसकी प्राथमिकता तिथि पेटेंटी के दावे से पहले है; (घ) जहां तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार उस दावे

की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था।स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक प्रक्रिया से संबंधित एक आविष्कार जिसके लिए एक पेटेंट प्रदान किया जाता है, यह माना जाएगा कि दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था, यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई उत्पाद पहले से ही उस तारीख से पहले भारत में आयात किया गया था, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया है।

(ई) कि जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से खंड (बी) में उल्लिखित विषय को ध्यान में रखते हुए या दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में क्या उपयोग किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए कोई आविष्कारात्मक कदम शामिल नहीं है;

(च) कि पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है;

(छ) कि पूर्ण विनिर्देशन पर्याप्त रूप से और स्पष्ट रूप से आविष्कार या उस विधि का वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे किया जाना है;

इसके बाद ही 8 फरवरी 2022 को, जब सनशाइन और नैटको के उपरोक्त पोस्ट ग्रांट विरोध अभी भी पेटेंट के विद्वान महानियंत्रक के समक्ष लंबित थे, श्री खेड़ा के अनुसार, एलॉयज़ वोबेन 2 में निर्णय के पैरा 19 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेटेंट रखने का अभियोक्ता का अधिकार, पेटेंट के खिलाफ दायर पोस्ट ग्रांट विरोधों के अनुकूल निपटान पर ही स्पष्ट हो जाएगा। अभियोक्ता का उल्लंघन का मुकदमा दायर करने का अधिकार उसके बाद ही सामने आएगा। वह अलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में समापन सजा पर विशेष भरोसा रखता है, जिसमें कहा गया है कि खंड 25 (2) के तहत

कार्यवाही लंबित होने पर उल्लंघन का मुकदमा दायर किए जाने की संभावना नहीं है और यह काफी असंभव है।

13. श्री खेरा भी, इस संदर्भ में, एक के आदेश पर निर्भर करते हैं फार्माकोसमॉस होल्डिंग ए/एस बनाम ला में इस न्यायालय की पीठ का समन्वय करें रेनाॅन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड 4.जैसा कि वर्तमान मामले में, फार्माकोस्मोस होल्डिंग 4 में प्रतिवादी ने भी मुकदमे की स्थिरता पर विवाद मुकदमाने की मांग की, जो एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 पर आधारित है। उक्त परिच्छेद को निकालने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4 के पैरा 12 से 19 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

—12.मैंने प्रतिवादी नं. के वकील से पूछताछ की है। 2/आवेदक, जो अब एकमात्र प्रतिवादी है, क्या पेटेंट के विरोध में पोस्ट ग्रांट की कोई जांच या कड़ी प्रवेश प्रक्रिया है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि जब तक कि कोई कड़ी प्रवेश प्रक्रिया नहीं है, केवल पोस्ट ग्रांट दाखिल करना है।

(ज) कि पेटेंटी खंड 8 द्वारा अपेक्षित जानकारी नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा है या उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो किसी भी सामग्री में विशेष रूप से उसकी जानकारी के लिए गलत थी;

(i) कि कन्वेंशन आवेदन पर दिए गए पेटेंट के मामले में, पेटेंट के लिए आवेदन किसी कन्वेंशन देश में या भारत में किए गए आविष्कार के लिए संरक्षण के लिए पहले आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर पेटेंट प्राप्तकर्ता या एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था जिससे वह शीर्षक प्राप्त करता है;

(जे) कि पूर्ण विनिर्देशन आविष्कार के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा या गलत उल्लेख नहीं करता है;

((ट) जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार का अनुमान भारत में या कहीं और किसी स्थानीय या स्वदेशी

समुदाय के भीतर उपलब्ध ज्ञान, मौखिक या अन्यथा, को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

लेकिन किसी अन्य आधार पर नहीं।

प्रास्थगन को पेटेंट प्राप्तकर्ता के अधिकारों को रोकने या रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13. प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक का कहना है कि पेटेंट नियंत्रक पेटेंटी को नोटिस जारी करने से पहले अनुदान के बाद के विरोध की जांच करता है।

14. भले ही ऐसा हो, जब तक कि केवल पेटेंटी के अधिकारों को रोकने के उद्देश्य से दायर तुच्छ पोस्ट ग्रांट विरोध को सीमित रूप से खारिज नहीं किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया या ऐसी व्याख्या पेटेंटी के लिए भारी कठिनाई का कारण बनेगी।

15. मुझे यह भी आश्चर्य हुआ है कि यदि कोई पेटेंटी पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से वंचित हो जाता है, तो जिस क्षण पेटेंट के लिए एक पोस्ट ग्रांट विरोध पेटेंट नियंत्रक के पास दायर किया जाता है और उसविचाराधीनता होने तक, क्या यह पेटेंट की वैधता के 20 वर्षों की वैधानिक अवधि में कटौती करेगा और उसे छोटा करेगा। इस प्रकार मैंने यह भी पूछा है कि क्या पेटेंट की वैधता की अवधि अनुदान के बाद के विरोध के निपटारे में लिए गए समय तक बढ़ाई गई है। 16. हालांकि प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक का कहना है कि यह उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करता है, लेकिन यह जांच करने पर कि क्या अधिनियम में इस आशय का कोई प्रावधान है कि अनुदान के बाद विरोध दर्ज करने पर, पेटेंट की अवधि बंद हो जाती है, यह बताता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

17. अभियोक्ता के वकील का कहना है कि अलॉयज वोबेन 2 में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख, हालांकि तब से असंख्य निर्णयों में किया गया है, लेकिन कभी भी इस तरह से व्याख्या नहीं की गई है और वह इस संबंध में मामले के कानून का हवाला देना चाहेंगे।

18. प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक यह भी बताता है कि वह योजना दिखाना चाहेगी।

19. मैं अन्यथा कह सकता हूं कि पैरा नं. की भाषा। 19. उपरोक्त निर्णय स्पष्ट है और भले ही मैंने उपरोक्त संदेहों को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उससे बाध्य हूं और अभियोक्ता को शायद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा॥

(जोर दिया गया)

14. श्री खेड़ा ने उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया है बॉम्बे की अदालत ने सर्गी ट्रांसफॉर्मर विस्फोट रोकथाम प्रौद्योगिकी प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड.सीटीआर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5

(— सर्गी, इसके बाद), साथ ही 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत सिविल अपील, **4 2019 (78) पी. टी. सी. 329 सी. एस. (सी. एम. एम.)** एस. एल. पी. (सी) 34749-34751/2015, जो उक्त निर्णय से उत्पन्न हुआ, निपटाया जा सकता है।

15. श्री खेरा का निवेदन है, इसलिए, एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए, न तो अभियोक्ता को अभी तक मुकदमे के पेटेंट का मुकदमा करने का अधिकार है, न ही अभियोक्ता इस स्तर पर उल्लंघन का मुकदमा दायर कर सकता है, भले ही सनशाइन और नैटको द्वारा दायर पोस्ट ग्रांट विरोध लंबित हैं।

16. दूसरी ओर, वादियों के विद्वान वकील श्री प्रवीण आनंद पेटेंट अधिनियम की खंड 11ए (3) के प्रावधान पर भरोसा करते हैं, जिसमें कहा गया है:

—बशर्ते कि आवेदक पेटेंट दिए जाने तक उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का हकदार नहीं होगा।।

इस प्रकार, श्री प्रवीण आनंद प्रस्तुत करते हैं, उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने पर एकमात्र वैधानिक प्रतिबंध, संबंधित पेटेंट का अनुदान है; दूसरे शब्दों में, पेटेंटी पेटेंट दिए जाने के बाद ही उल्लंघन की कार्रवाई शुरू कर सकता है। एक बार पेटेंट दिए जाने के बाद, पेटेंट अधिनियम में, पेटेंट प्राप्तकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके लिए उसे कथित उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक पल और इंतजार करने की आवश्यकता होती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि पेटेंट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पेटेंट के अनुदान से एक वर्ष की समाप्ति तक या पेटेंट के अनुदान के बाद दायर किसी भी अनुदान के बाद के विरोध की समाप्ति तक उल्लंघन के लिए मुकदमा करने के पेटेंट प्राप्तकर्ता के अधिकार को रोकता है।

17. जहां तक अलॉयज वोबेन 2 में निर्णय का संबंध है, श्री प्रवीण आनंद प्रस्तुत करते हैं कि उक्त निर्णय को सीएस (सीओएमएम) 101/2022 44 के पृष्ठ 9 द्वारा अलग किया गया है। 5 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 6984 सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) नोवार्टिस एजी बनाम नैटको लिमिटेड 6 में इस न्यायालय की दो समन्वय पीठें और सी. डी. ई. एशिया लिमिटेड बनाम.टेरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 7.इन दोनों निर्णयों में, उन्होंने प्रस्तुत करता है, यह अभिनिर्धारित करता है कि, भले ही पेटेंट रखने का अधिकार केवल अनुदान के बाद के विरोध की अस्वीकृति पर स्पष्ट हो जाता है, फिर भी अधिकार, पेटेंट दिए जाने के क्षण में अस्तित्व में आता है, और एक बार ऐसा अधिकार अस्तित्व में आने के बाद, पेटेंट धारक उल्लंघन के लिए मुकदमा करने का हकदार है, जहां वह इसे पाता है। ऐसी स्थिति में, उसे पेटेंट देने की

तारीख से एक साल की समाप्ति तक या अनुदान के बाद दायर किए गए किसी भी विरोध के निपटारे तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

18. इसके अलावा, श्री प्रवीण आनंद प्रस्तुत करते हैं कि अलॉयज वोबेन 2 में विवादग्रस्त मुद्दा प्रत्यर्थी योगेश मेहरा का उनके खिलाफ अपीलकर्ता अलॉयज वोबेन द्वारा शुरू किए गए उल्लंघन मुकदमे में जवाबी मुकदमा दायर करने का अधिकार था, जबकि पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत दायर पिछली निरसन याचिका थी।

6 सीएस (कॉम) 299/2019 में दिनांक 2 मई 2019 का आदेश

7 MANU/DE/0584/2020

8 64.पेटेंट का निरसन।-

(1) इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन, एक पेटेंट, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दिया गया हो, किसी भी इच्छुक व्यक्ति या केंद्र सरकार की याचिका पर या उच्च न्यायालय द्वारा पेटेंट के उल्लंघन के मुकदमा मुकदमे में जवाबी दावे पर निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रद्द किया जा सकता है, अर्थात्

-

(क) कि आविष्कार, जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, भारत में दिए गए किसी अन्य पेटेंट के पूर्ण विनिर्देशन में निहित पूर्व प्राथमिकता तिथि के वैध दावे में दावा किया गया था;

(ख) कि पेटेंट किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर दिया गया था जो इसके लिए आवेदन करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हकदार नहीं है;

(ग) कि पेटेंट याचिकाकर्ता या किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन में गलत तरीके से प्राप्त किया गया था जिसके तहत या जिसद्वारा से वह दावा करता है;

(घ) कि पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक आविष्कार नहीं है;

(ड) दावा की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था या खंड 13 में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज में भारत में या कहीं और क्या प्रकाशित किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार नया नहीं है;

(च) जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है या इसमें कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है, जो भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था या जो दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में या कहीं और प्रकाशित किया गया था;

(छ) कि आविष्कार, जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, उपयोगी नहीं है;

(ज) कि पूर्ण विनिर्देशन पर्याप्त रूप से और निष्पक्ष रूप से आविष्कार और उस विधि का वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे किया जाना है, अर्थात्, पूर्ण विनिर्देशन में निहित विधि का विवरण या आविष्कार के काम करने के लिए निर्देश अपने आप में उस व्यक्ति को सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो भारत में उस कला में औसत कौशल और औसत ज्ञान रखता है जिसके लिए आविष्कार सीएस (सीओएमएम)

लंबित है। श्री आनंद प्रस्तुत करते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी योगेश मेहरा एक साथ एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित मुकदमे में एक प्रतिसंहरण याचिका और जवाबी दावे पर मुकदमा नहीं चला सकते। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी खंड 64 (1) के तहत प्रतिसंहरण याचिका दायर करने के लिए पहले से ही निर्वाचित होने के कारण जवाबी दावा दायर नहीं कर सकता है।

19. श्री आनंद प्रस्तुत करते हैं कि अलॉयज वोबेन 2 में उच्चतम न्यायालय कभी भी इस मुद्दे से चिंतित नहीं था कि क्या उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (1) के तहत किसी अन्य पक्ष द्वारा दायर अनुदान के बाद

का विरोध लंबित था। न ही, वे प्रस्तुत करते हैं, ऐसा मुद्दा कभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया या बहस की गई। श्री आनंद प्रस्तुत करते हैं कि, यदि उच्चतम न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करने का इरादा होता कि यदि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (1) के तहत दायर की गई निरसन याचिका लंबित थी, तो उक्त निरसन याचिका के निपटारे तक पेटेंटी द्वारा कोई उल्लंघन मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, तो ऐसा अभिनिर्धारित किया जाता। श्री आनंद प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है।

यह आविष्कार पर काम करने से संबंधित है, या यह कि यह इसे करने के सर्वोत्तम तरीके का खुलासा नहीं करता है जो पेटेंट के लिए आवेदक को ज्ञात था और जिसके लिए वह संरक्षण का दावा करने का हकदार था;

(i) कि पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे का दायरा पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है या कि पूर्ण विनिर्देशन का कोई भी दावा विनिर्देशन में प्रकट किए गए मामले पर निष्पक्ष रूप से आधारित नहीं है;

(जे) कि पेटेंट एक गलत सुझाव या प्रतिनिधित्व पर प्राप्त किया गया था;

(के) कि पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है;

((च) जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार का उपयोग दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले, उप-धारा (3) में उल्लिखित के अलावा, भारत में गुप्त रूप से किया गया था;

(एम) कि पेटेंट के लिए आवेदक नियंत्रक को खंड 8 द्वारा आवश्यक जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो किसी भी सामग्री में विशेष रूप से उसकी जानकारी के लिए गलत थी;

(एन) कि आवेदक ने खंड 35 के तहत पारित गोपनीयता के लिए किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया या खंड 39 के उल्लंघन में भारत के बाहर पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन किया या किया गया;

(ओ) कि खंड 57 या खंड 58 के तहत पूर्ण विनिर्देश में संशोधन करने की अनुमति धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी;

(पी) कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत या भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा या गलत उल्लेख नहीं करता है;

((क) जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार का अनुमान भारत में या कहीं और किसी स्थानीय या स्वदेशी समुदाय के भीतर उपलब्ध ज्ञान, मौखिक या अन्यथा, को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

अलॉयज वोबेन 2 में पैरा 19 या कहीं और स्पष्ट खोज, या यहाँ तक कि अवलोकन।वे प्रस्तुत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जानबूझकर 'क्रिस्टलाइज्ड' शब्द का उपयोग किया है, जो कि विविध अर्थों वाला शब्द है।यहां तक कि एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में समापन अवलोकन, वह प्रस्तुत करता है, केवल यह देखता है कि यह संभावना नहीं थी कि उल्लंघन का मुकदमा दायर किया जाएगा, भले ही खंड 25 (2) के तहत निरसन याचिकाएं लंबित थीं।वे प्रस्तुत मुकदमाते हैं कि उक्त टिप्पणियां इस तरह के उल्लंघन के मुकदमे को दायर मुकदमाने से नहीं रोकती हैं।

20. सबसे ऊपर, श्री आनंद प्रस्तुत करते हैं, अलॉयज़ वोबेन 2 के पैरा 19 में टिप्पणियां, जिन पर श्री खेरा भरोसा करते हैं, केवल आज्ञाकारी आदेश हैं, जो उनके अनुसार, बाध्यकारी नहीं हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। न्यायालय ने करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुर एजुकेशनल सोसाइटी 9 में अपने हालिया निर्णय में कहा।

विश्लेषण

एलॉयज वोबेन 2

21. एलॉयज वोबेन 2 के तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले अपीलकर्ता, डॉ. एलॉयस वोबेन, कई पेटेंट किए गए आविष्कारों के निडर आविष्कारक थे। एनरकॉन इंडिया लिमिटेड (-एनरकॉन, इसके बाद) ने पूर्ववर्ती बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई. पी. ए. बी.) के समक्ष 19 निरसन याचिकाएं दायर कीं, जिसमें एलॉयस वोबेन को दिए गए 19 पेटेंट को रद्द करने की मांग की गई थी। बाद में, दूसरी ओर, एलॉयस वोबेन ने एनरकॉन के खिलाफ 10 उल्लंघन के मुकदमे दायर किए, जिसमें एनरकॉन द्वारा उनके पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एनरकॉन ने एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित उक्त मुकदमों में प्रतिवाद दायर किया,

प्रत्येक मामले में, संबंधित मुकदमे में मुकदमा किए गए पेटेंट को रद्द करने की मांग करना। इसके अतिरिक्त, एनरकॉन ने एलॉयस वोबेन के पेटेंट को रद्द करने की मांग करते हुए चार और निरसन याचिकाएं दायर कीं। इसलिए जो स्थिति सामने आई, वह यह थी कि एनरकॉन द्वारा एलॉयस वोबेन के खिलाफ 23 निरसन याचिकाएं दायर की गई थीं, एनरकॉन के खिलाफ एलॉयस वोबेन द्वारा 10 उल्लंघन मुकदमे दायर किए गए थे और उक्त 10 उल्लंघन मुकदमों में से प्रत्येक में, एनरकॉन ने प्रतिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमे में मुकदमा किए गए पेटेंट को रद्द करने की मांग की गई थी।

22. निर्विवाद रूप से, इसलिए, एलॉयस वोबेन को दिए गए किसी भी पेटेंट को चुनौती देते हुए, अनुदान के बाद कोई विरोध दायर नहीं किया गया था।

23. यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मुद्दों की पहचान की गई है, मुख्य मुकदमा से, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या एनरकॉन उसी पेटेंट के संबंध में एलॉयस वोबेन द्वारा मुकदमे की स्थापना के समक्ष पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत दायर निरसन याचिकाओं और एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित मुकदमों में उसके द्वारा दायर जवाबी दावों को एक साथ बनाए रख सकता है।

24. सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक बार पेटेंट दिए जाने के बाद, अनुदान को या तो खंड 64 (1) के तहत निरसन याचिका या पेटेंट अधिनियम की खंड 27 (2) के तहत अनुदान के बाद के विरोध के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और विरोध किया जा सकता है। जबकि एक प्रतिसंहरण याचिका केवल एक इच्छुक व्यक्ति द्वारा शुरू की जा सकती है, अनुदान के बाद विरोध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। हालाँकि, इस भेद को वर्तमान मामले में हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।

25. इसके अतिरिक्त, पेटेंट के अनुदान को चुनौती दे सकता है। प्रतिदावे का तरीका, पेटेंटी द्वारा उल्लंघन का मुकदमा दायर किए जाने की स्थिति में। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक प्रदत्त पेटेंट को तीन पक्षों से चुनौती दी जा सकती है।

26. इसी पृष्ठभूमि में एलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 की सराहना की जानी चाहिए। इसके तत्वों में विभाजित, यह देखा जाता है कि, पैरा 19 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

(i) एक व्यक्ति जिसने पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत पेटेंट के लिए अनुदान के बाद विरोध दायर किया है, उसके बाद, उसी पेटेंट को चुनौती देते हुए, खंड 64 (1) के तहत, या पेटेंटी द्वारा स्थापित किसी भी उल्लंघन मुकदमे में जवाबी मुकदमा दायर नहीं कर सकता है (क्योंकि खंड 64 को पेटेंट अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन किया गया है)।

((ii) पेटेंट के अनुदान के निर्णय को पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन पर अंतिम रूप दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रक का निर्णय होता है।

((iii) पेटेंट के अनुदान का प्रकाशन, हालांकि, पेटेंटी के अधिकार को स्पष्ट नहीं करता है,

(iv) पेटेंट रखने के पेटेंट प्राप्तकर्ता के अधिकार को केवल तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब-खंड 27 (2) के तहत अनुदान के बाद के विरोध के माध्यम से पेटेंट के अनुदान के लिए उठाई गई चुनौतियों का निपटान पेटेंट धारक के लाभ के लिए किया जाता है, या, वैकल्पिक रूप से, यदि ऐसा कोई अनुदान के बाद का विरोध दायर नहीं किया जाता है, तो, पेटेंट के अनुदान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर।

(v)-केवल पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत विचार की गई प्रक्रिया की पराकाष्ठा पेटेंट को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है।

(vi)-इसलिए, यह असंभव और काफी असंभव है कि कोई भी CS (COMM) खंड 25 (2) के तहत कार्यवाही लंबित है, या पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर उल्लंघन का मुकदमा दायर किया जाएगा।

27. मैं श्री प्रवीण आनंद की इस दलील से पूरी तरह सहमत हूं कि पेटेंट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो एक पेटेंटी को, जिसे पेटेंट दिया गया है, उल्लंघन के लिए तुरंत मुकदमा करने से रोकता है, जहां वह उल्लंघन होने का अनुभव करता है। समान रूप से, मैं इस बात से सहमत हूं कि पेटेंट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से पहले पेटेंट प्राप्तकर्ता को पेटेंट के अनुदान से एक वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो, या यदि उक्त अवधि के भीतर कोई अनुदान के बाद का विरोध दायर किया गया हो, तो पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से पहले, इस तरह के अनुदान के बाद के विरोध के बाद कार्यवाही की अनुकूल परिणति के लिए।

28. श्री आनंद ने जो कहा है उसके पूरक के रूप में, मैं यह भी देख सकता हूं कि यदि एक पेटेंटी, जिसे पेटेंट दिया गया है, को कथित उल्लंघनकर्ता पर मुकदमा करने से

पहले, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इंतजार करना पड़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप पेटेंटी को पेटेंट के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जा सकता है। श्री आनंद का कहना सही है कि पेटेंट अधिनियम की खंड 11ए का प्रावधान केवल पेटेंट दिए जाने तक उल्लंघन के मुकदमे को लागू मुकदमाने से रोकता है। इस मुकदमा, परिणाम यह होगा कि एक बार पेटेंट दिए जाने के बाद, उल्लंघन का मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह तर्कसंगत प्रतीत होगा, और स्वयं पेटेंट अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार होगा। उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने से पहले पेटेंटी को एक साल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता, स्पष्ट रूप से, उल्लंघनकर्ताओं को एक साल की उक्त अवधि के दौरान पेटेंट का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने के लिए एक खुला क्षेत्र प्रदान करेगी, जिसमें पेटेंटी के पास इसके खिलाफ कोई कानूनी उपाय नहीं होगा।

29. लेकिन फिर, एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 का क्या?

30. उस मुद्दे से निपटने से पहले, फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और विभिन्न चरणों में पारित निर्णयों/आदेशों का उल्लेख करना आवश्यक है। सर्गी 5.

फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4

31. फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4 के पारस 11 से 19 इस प्रकार हैं:

—11. प्रतिअभियोक्ता के वकील नं। 2/आवेदक का कहना है कि वाद की स्थापना से पहले दायर अभियोक्ता के विषय पेटेंट के मुकदमा अनुदान के बाद विरोध, पेटेंट नियंत्रक के समक्ष विचाराधीन है और पैरा संख्या के अनुसार। एलॉयज वोबेन 2 का 19 (जैसा कि नीचे दिया गया है), पेटेंट के उल्लंघन के मुकदमा यह मुकदमा तब तक नहीं है जब तक कि उक्त अनुदान के बाद के विरोध का निर्णय नहीं हो जाता है।

—19. यदि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा कोई कार्यवाही शुरू की गई है, तो यह उसी व्यक्ति के पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत रद्द याचिका दायर करने के अधिकार को ग्रहण कर लेगा। और साथ ही, पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत दिए गए अधिकार का आह्वान करने के लिए, एक-प्रति-दावा दायर करने के लिए (एक-उल्लंघन मुकदमे के जवाब में, एक पेटेंट को रद्द करने की मांग करने के लिए)। यह, हमारे विचार में, पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) की शुरुआत में दिखाई देने वाले इन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन शब्दों का स्वाभाविक प्रभाव होगा। और यदि उपरोक्त अर्थ इन शब्दों को नहीं दिया जाता है—इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, तो वे अनावश्यक और अनावश्यक होंगे। हालाँकि ऊपर उल्लिखित स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त स्थिति, हमारे विचार में, कभी भी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, पेटेंट अधिनियम की खंड 25, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, पेटेंट के अनुदान के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करती है। प्रक्रिया आवेदन दाखिल करने के साथ शुरू होती है। दूसरा चरण मांगे गए पेटेंट के विवरण के प्रकाशन पर विचार करता है। अगले चरण में विरोध (पेटेंट के अनुदान के लिए) के माध्यम से अभ्यावेदन दाखिल करने की परिकल्पना की गई है। यह नियंत्रक द्वारा पेटेंट देने या अस्वीकार करने के दृढ़ संकल्प में आगे बढ़ता है। नियंत्रक के निर्णय से अनुदान (सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) 101/2022 44 का पृष्ठ 16 प्रकाशित होता है। पेटेंट)। यह प्रक्रिया पेटेंट के अनुदान के निर्णय को अंतिम रूप देती है। फिर भी, यह अंततः पेटेंट धारक के अधिकार को स्पष्ट नहीं करता है। अनुदान के प्रकाशित होने के बाद, कोई भी इच्छुक व्यक्ति पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर विरोध का नोटिस जारी कर सकता है। यदि और कब, पेटेंट के अनुदान के लिए उठाई गई चुनौतियों का अनुकूल निपटान किया जाता है, तो पेटेंट धारक के लाभ के लिए, पेटेंट रखने का अधिकार तब और फिर ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसी तरह, यदि विरोध की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर, अनुदान को स्पष्ट माना जाएगा। इस प्रकार, केवल पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत

विचार की गई प्रक्रिया की पराकाष्ठा, पेटेंट को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है। इसलिए, यह असंभव और काफी असंभव है कि उल्लंघन का मुकदमा दायर किया जाएगा, जबकि खंड 25 (2) के तहत कार्यवाही लंबित है, या पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन की तारीख के एक साल के भीतर॥

(जोर दिया गया)

12. मैंने प्रतिवादी नं. के वकील से पूछताछ की है। 2/आवेदक, जो अब एकमात्र प्रतिवादी है, चाहे पेटेंट के प्रास्थगन में पोस्ट ग्रांट की कोई जांच या कड़ी प्रवेश प्रक्रिया हो, क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि जब तक कि एक सख्त प्रवेश प्रक्रिया नहीं है, केवल पोस्ट ग्रांट प्रास्थगन दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या पेटेंट प्राप्तकर्ता के अधिकारों को रोक कर रखा जाना चाहिए।

13. प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक का कहना है कि पेटेंट नियंत्रक पेटेंटी को नोटिस जारी करने से पहले अनुदान के बाद के विरोध की जांच करता है।

14. भले ही ऐसा हो, जब तक कि केवल पेटेंटी के अधिकारों को रोकने के उद्देश्य से दायर तुच्छ पोस्ट ग्रांट विरोध को सीमित रूप से खारिज नहीं किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया या ऐसी व्याख्या पेटेंटी के लिए भारी कठिनाई का कारण बनेगी।

15. मुझे यह भी आश्चर्य हुआ है कि यदि कोई पेटेंटी पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से वंचित हो जाता है, तो जिस क्षण पेटेंट के लिए एक पोस्ट ग्रांट विरोध पेटेंट नियंत्रक के पास दायर किया जाता है और उसविचाराधीनता होने तक, क्या यह पेटेंट की वैधता के 20 वर्षों की वैधानिक अवधि में कटौती करेगा और उसे छोटा करेगा। इस प्रकार मैंने यह भी पूछा है कि क्या पेटेंट की वैधता की अवधि अनुदान के बाद के विरोध के निपटारे में लिए गए समय तक बढ़ाई गई है।

16. हालांकि प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक का कहना है कि यह उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करता है, लेकिन यह जांच करने पर कि क्या अधिनियम में इस आशय

का कोई प्रावधान है कि अनुदान के बाद विरोध दर्ज करने पर, पेटेंट की अवधि बंद हो जाती है, यह बताता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

17. अभियोक्ता के वकील का कहना है कि अलॉयज वोबेन 2 में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख, हालांकि तब से असंख्य निर्णयों में किया गया है, लेकिन कभी भी इस तरह से व्याख्या नहीं की गई है और वह इस संबंध में मामले के कानून का हवाला देना चाहेंगे।

18. प्रतिवादी के वकील नं। 2/आवेदक यह भी बताता है कि वह योजना दिखाना चाहेगी।

19. मैं अन्यथा कह सकता हूं कि पैरा नं. की भाषा। 19. उपरोक्त निर्णय स्पष्ट है और भले ही मैंने उपरोक्त संदेहों को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उससे बाध्य हूं और अभियोक्ता को शायद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।

20. अनुरोध पर, 26 जुलाई, 2019 को सूचीबद्ध करें ॥

(पैरा 19 में जोर दिया गया है)

32. फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4 के पैरा 19 पर निर्भरता रखते हुए, यह स्पष्ट है कि श्री खेड़ा केवल पुआल पकड़ रहे हैं। पैरा 19 प्रतिबिम्ब की अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है, वह भी अनिर्णायक है-जैसा कि मामले की कार्यवाही में अंतर्वर्ती चरण में पारित आदेश में-शायद '-शब्द के उपयोग से स्पष्ट है। मुझे सूचित किया गया है कि **फार्माकोसमॉस होल्डिंग⁴** में मुकदमे का आखिरकार समझौता करके मुकदमा कर दिया गया। चाहे जो भी हो, **फार्माकोसमॉस होल्डिंग⁴** के पैरा 19 में निहित अवलोकन स्पष्ट रूप से किसी भी पूर्ववर्ती मूल्य से पूरी तरह से रहित हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुभव की गई असुविधा, पैरा 19 में उक्त अस्थायी अवलोकन दर्ज करते समय भी, उससे पहले के पैराग्राफ से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। जैसा कि उक्त पैराग्राफ में देखा गया है, एक सख्त प्रवेश प्रक्रिया की अनुपस्थिति में, जो तुच्छ आपत्तियों की सीमित

अस्वीकृति की अनुमति देती है, यह खतरनाक होगा, और पेटेंटी के लिए बहुत प्रतिकूल होगा, अगर उसे पेटेंट दिए जाने के बाद भी एक साल की अवधि के लिए उल्लंघन को सहन करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी नोट किया है, ऐसी स्थिति में, पेटेंट का जीवन, जो केवल 20 वर्ष है, उस अवधि तक कम हो जाएगा जिसके लिए पेटेंटी को उल्लंघन को बर्दाश्त करना होगा, चाहे वह एक वर्ष हो (जहां कोई सीएस (सीओएमएम) न हो)

अनुदान के बाद का विरोध उक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है) या, इससे भी बदतर, एक अनिश्चित अवधि जो अनुदान के बाद के विरोध के निपटारे में खर्च की जाएगी (जहां अनुदान के बाद का विरोध एक वर्ष के भीतर दायर किया जाता है)।

33. यदि, इसलिए, पैरा 19 में निहित अस्थायी अवलोकन का जायजा लेना है, तो **फार्माकॉसमॉस होल्डिंग⁴** के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निहित विचारों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए; अधिक सटीक रूप से, पैरा 12 से 17।

34. उसी समय, भले ही **अलॉयस वोबेन²** के पैरा 19 को श्री खेड़ा द्वारा सुझाई गई व्याख्या दी जाए, न्यायालय को आगे उक्त पैरा के पूर्ववर्ती मूल्य और श्री प्रवीण आनंद द्वारा दिए गए इस तर्क की जांच करनी होगी कि उसमें निहित टिप्पणियां केवल आज्ञाकारी हैं।

सर्गी⁵

35. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **फार्माकॉसमॉस होल्डिंग⁴** की तरह, 1 दिसंबर, 2015 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का आदेश, जिसे श्री खेड़ा ने **सरगी⁵** में उद्धृत किया है, भी एक अंतर्वर्ती आदेश है, जिसमें अपील को स्वीकार किया गया है और अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है।

.मुकदमा

उक्त मुकदमे में जवाबी मुकदमा दायर किया।²³ अक्टूबर 2015 को, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा प्रदान की, जिसमें सेर्गी को किसी भी तरह से आई. एन. '302 का उपयोग करने से रोकते हुए कहा गया कि इस तरह के उपयोग से पेटेंट का उल्लंघन होगा। सर्गी ने खण्ड पीठ में अपील की।

37. सेर्गी ने खण्ड पीठ के समक्ष दलीलों में से एक के रूप में यह याचिका दायर की कि सेर्गी ने आई. एन. **एलॉयस वोबेन**² के पैरा 19 पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि सी. टी. आर. द्वारा स्थापित मुकदमा-असंभव और बनाए रखने योग्य नहीं था। सर्गी द्वारा प्रस्तुत अन्य दलीलें वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सी. टी. आर. ने अपने जवाब में अलॉयज के पैरा 19 के मामले के तथ्यों पर लागू होने पर विवाद किया। **वोबेन**².

38. विद्वत एकल न्यायाधीश ने खण्ड पीठ के समक्ष अपील के तहत आदेश में, अलॉयस वोबेन के अनुच्छेद 19 में उल्लेख किया था कि उनके समक्ष मुकदमा ठीक उसी प्रकृति का था जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी, जहां, साथ ही, आई. एन. '302 के खिलाफ एक अनुदान के बाद का विरोध, निरसन कार्यवाही और सर्गी द्वारा स्थापित एक जवाबी दावा लंबित था। उन्होंने आगे कहा कि- यदि पेटेंट का अनुदान समाप्त नहीं किया जाता है और पूछने के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं मिलती है, तो इसका पालन करना चाहिए कि केवल एक प्रतिवाद, विरोध या निरसन आवेदनों की विचाराधीनता किसी भी निषेधाज्ञा दावे को पराजित नहीं कर सकती है।

39. खण्ड पीठ ने कहा कि आई. एन. **सेर्गी सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.)**

योग्यता और कानून पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर, अपील को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े और अंतरिम राहत के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश के 23 अक्टूबर 2015 के

आदेश पर रोक लगा दी। जिस हद तक यह हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, खण्ड पीठ के फैसले ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

—(i) अपील स्वीकार की जाती है।

(ii) विज्ञापन अंतरिम राहत के माध्यम से हम निर्देश देते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 को पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जाएगी।

(iii) अपीलकर्ता को ट्रांसफॉर्मरों का निर्माण और सौदा जारी रखने का अधिकार है॥

40. सी. टी. आर. एस. एल. पी. (सी) 34749-34751/2015 के माध्यम से मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गया। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत में इस प्रकार टिप्पणी की:

—खण्ड पीठ के आदेश को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि खण्ड पीठ ने पक्षों की संबंधित दलीलों के गुणागुण पर ध्यान नहीं दिया है और केवल इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि जहां तक अपीलकर्ता को प्रश्रगत पेटेंट के अनुदान का संबंध है, प्रतिवादी ने पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत आपत्तियां दायर की हैं जो पेटेंट नियंत्रक के समक्ष लंबित हैं और केवल इसी आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी गई है॥

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को इस हद तक दरकिनार कर दिया कि उसने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश पर रोक लगा दी और खण्ड पीठ के फैसले में (ii) और (iii) को निम्नलिखित निर्देश के साथ प्रतिस्थापित किया:

—जब तक विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव की सूचना (प्रदर्शनी 5) और अन्य आवेदनों का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक अपीलकर्ता (वाद में प्रतिअभियोक्ता) अपने पेटेंट के मुकदमा अपने उत्पादों का निर्माण और बिक्री जारी रखेगा, लेकिन वाद के

प्रतिअभियोक्ता संख्या 1 अभियोक्ता के पेटेंट का उल्लंघन किए बिना, 15 नवंबर, 2011 को विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष पहले से दिए गए वचन के मुकदमा।

41. प्रभावी मुकदमा से, इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सी. टी. आर. के पेटेंट आई. एन. 305 के उल्लंघन के खिलाफ अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा को बहाल कर दिया, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया था, जबकि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत सी. टी. आर. के सूट पेटेंट के खिलाफ सर्गी द्वारा अनुदान के बाद विरोध, पेटेंट नियंत्रक के समक्ष लंबित था।

ओबिटर की याचिका

42. श्री प्रवीण आनंद ने यह तर्क देना चाहा कि **एलॉयस वोबेन**² में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद का मुद्दा यह था कि क्या एनरकॉन, जो पहले ही एलॉयस वोबेन के पेटेंट को रद्द करने के लिए आवेदन कर चुका है, उसी पेटेंट को रद्द करने की मांग करते हुए, उसके खिलाफ एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित उल्लंघन मुकदमों में जवाबी दावे कर सकता है। इस प्रकार, श्री आनंद का तर्क है कि पेटेंट अधिनियम की खंड 27 (2) के तहत अलॉयज वोबेन 2 में कोई पोस्ट ग्रांट विरोध कभी भी मुद्दा नहीं था। न ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी तर्क को संबोधित किया गया था कि क्या एक पेटेंटी को उल्लंघन का मुकदमा दायर करने से पहले एक साल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, या उसके पक्ष में कार्यवाही करने वाले पोस्ट ग्रांट विपक्ष के समापन तक। इसलिए, भले ही श्री खेड़ा के सुझाव के अनुसार अलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 की व्याख्या की जाए, श्री प्रवीण आनंद प्रस्तुत करते हैं कि उक्त पैरा में निहित उस आशय की टिप्पणियों को आज्ञाकारी आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, न कि निर्णय के अनुपात निर्णय के हिस्से के रूप में। आज्ञाकारी आदेश, वह प्रस्तुत करता है, बांधता नहीं है, जिसके लिए वह **कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल** का हवाला देता है **समाज**

द जजमेंट इन करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9

43. उच्चतम न्यायालय का 24 अप्रैल 2023 का निर्णय **कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9 का उदय दिनांकित निर्णय से हुआ।** 23 जनवरी 2023, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित **ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी बनाम करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 10**, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (-1996 अधिनियम) की खंड 11 के तहत ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी (-इसके बाद ओएसटीईएस) द्वारा स्थापित एक याचिका थी, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी। यह विवाद दो पट्टा समझौतों से उत्पन्न हुआ, जिसके तहत कुछ परिसरों को ओएसटीईएस द्वारा करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी (सी. आई. ई. एस.) को पट्टे पर दिया गया था। सी. आई. ई. एस. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों में यह याचिका थी कि मध्यस्थता समझौते पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई थी। इस बिंदु पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, **गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम तटीय समुद्री निर्माण और एस. एम. एस. टी. में अपने पहले के निर्णय के बाद इंजीनियरिंग लिमिटेड 11 आयोजित किया गया एस्टेट्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड चांदमारी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 12**, कि एक मध्यस्थता स्टाम्प रहित दस्तावेज़ में खंड तब तक अस्तित्वहीन और अप्रवर्तनीय था जब तक कि स्टाम्प शुल्क के मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता और अनुबंध पर भुगतान नहीं किया जाता।

विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्प में एक बाद के निर्णय में। 13, **सुप्रीम कोर्ट ने गारवेयर वॉल रोप्स 11 को मंजूरी दी।** हालांकि, एन. एन. में गारवेयर वॉल रोप्स 11 और एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स 12 को खारिज कर दिया गया। ग्लोबल मर्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिफ्लेम लिमिटेड 14 इस पहलू ने विद्या द्रोलिया 13 में लिए गए दृष्टिकोण पर भी संदेह किया और मामले को संविधान पीठ को

भेज दिया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, जैसा कि मुद्दा संविधान पीठ को संदर्भित किया गया था, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा रहा था।

10 मध्यस्थता मामला सं. 216/2021

11 (2019) 9 एससीसी 209

12 (2011) 14 SCC 66

13 (2021) 2 SCC 1

14 (2021) 4 SCC 379 CS (COMM)

44. उच्चतम न्यायालय के समक्ष, सी. आई. ई. एस. ने फिर से सेवा में दबाव डाला, **विद्या द्रोलिया¹³**. **विद्या द्रोलिया¹³** में निर्णय से प्रासंगिक अंशों को निकालने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, उक्त निर्णय में, उसने मध्यस्थता समझौते पर, अंतर्निहित अनुबंध के अनस्टैम्ड या अंडरस्टैम्ड होने के प्रभाव की जांच या निर्णय नहीं लिया था। उक्त मुद्दे का निर्णय **विद्या द्रोलिया¹³** में नहीं होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **विद्या द्रोलिया¹³** को उस बिंदु पर एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों को दर्ज किया:

—3. विद्या द्रोलिया 13 के फैसले में मध्यस्थता समझौते पर बिना मोहर वाले या कम मुहर वाले अंतर्निहित अनुबंध के प्रभाव के मुद्दे की जांच और निर्णय नहीं किया गया था। चूंकि विद्या द्रोलिया 13 में इस मुद्दे और प्रश्न का निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह निर्णय इस प्रश्न पर एक मिसाल नहीं है।

4. विद्या द्रोलिया 13 ने गरवारे वॉल रोप्स 11 के मामले में फैसले का उल्लेख किया था, लेकिन एक अलग संदर्भ में, जैसा कि विद्या द्रोलिया 14 में फैसले के पैराग्राफ 146 और 147.1 से स्पष्ट है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

—146. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या खंड 11 में 'अस्तित्व' शब्द केवल अनुबंध गठन को संदर्भित

करता है (क्या कोई मध्यस्थता समझौता है) और प्रवर्तन (वैधता) के प्रश्न को बाहर करता है और इसलिए बाद वाला संदर्भ स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या शब्द के स्पष्ट अर्थ-अस्तित्व से समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर यह मानना भी समान रूप से संभव है कि किसी समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि वह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे अदालत द्वारा पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए खारिज करके लागू किया जाएगा। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या परिभाषा खंड सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे। अस्तित्व की एक उचित और न्यायपूर्ण व्याख्या के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते के लिए लागू संदर्भ, उद्देश्य और प्रासंगिक कानूनी मानदंडों को समझने की आवश्यकता होती है। लिखित रूप में प्रमाणित समझौते का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करना करने और उनका पालन करना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक अप्रवर्तनीय दस्तावेज़ के आधार पर अधिकार पर मुकदमा करें और दावा करें। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है।

147.1. गरवारे वॉल रोप्स 11 में, इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7

(2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया था, हालांकि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियों को उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण, हम इसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे:(एस. सी. सी. पी. 238)

—29. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में यह फैसला कं. लिमिटेड बनाम।हुंडई इंग।& निर्माण कंपनी लिमिटेड ¹⁵, इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो विशेष रूप से विचाराधीन था वह एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता देयता स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड मौजूद था-इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक कानून के मामले के रूप में मौजूद नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं। यह तर्क कि खंड 11 (6-ए) खंड 8, खंड 16 और खंड 45 के विपरीत अस्तित्व से संबंधित है, जो एक मध्यस्थता समझौते की वैधता से संबंधित है, इस अदालत की अभिव्यक्ति की समझ से जवाब मिलता है-हुंडई एंग में अस्तित्व। 15 मामला, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया।।

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।

5. विद्या द्रोलिया 13 में उपरोक्त पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि गरवारे वॉल रोप्स 11 में निर्णय का संदर्भ 'अस्तित्व' शब्द की व्याख्या करने के लिए किया गया था, और क्या एक 'अमान्य' मध्यस्थता समझौते को अस्तित्व में कहा जा सकता है? यह जाँच यह तय करने के लिए थी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का निर्णय कौन करता है।

6. कानून के प्रस्ताव के रूप में किसी निर्णय में आज्ञाकारी आदेश और अनुपात निर्णय के बीच के अंतर की इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा जांच की गई है, लेकिन हम दो का उल्लेख करना चाहेंगे, **अर्थात्, गुजरात राज्य बनाम उपयोगिता उपयोगकर्ता कल्याण संघ 16 और जयंत वर्मा बनाम भारत संघ 17।**

7. गुजरात राज्य 16 में पहला निर्णय लागू होता है जिसे कहा जाता है-व्युत्क्रम परीक्षण यह पहचानने के लिए कि एक निर्णय में अनुपात निर्णय क्या है। यह जांचने के लिए कि क्या कानून के किसी विशेष प्रस्ताव को मामले के अनुपात निर्णय के रूप में माना जाना है, प्रस्ताव को उल्टा किया जाना है, यानी निर्णय के पाठ से हटा दिया जाना है जैसे कि यह मौजूद नहीं था। यदि प्रस्ताव की जांच किए बिना भी मामले का निष्कर्ष वही रहा होगा, तो इसे मामले का अनुपात निर्णय नहीं माना जा सकता है।

8. जयंत वर्मा 17 में, इस न्यायालय ने पहले एक मामले का उल्लेख किया है। **दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 18 मामले में इस न्यायालय का निर्णय** कि यह प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष नहीं हैं, बल्कि तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान हैं, जो निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है और एक उदाहरण के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि निष्कर्ष भी एक मिसाल के रूप में काम नहीं करता है, हालांकि यह रेस जुडिकाटा के रूप में काम करता है। इस प्रकार, यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक न्यायाधीश के निर्णय में एक कानूनी मिसाल के रूप में बाध्यकारी एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से,

किसी निर्णय का विश्लेषण करना और उससे आज्ञाकारी आदेश को अलग करना महत्वपूर्ण है॥

45. यदि कोई उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ जोड़ता है, तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अनुबंध में मध्यस्थता खंड पर, अंतर्निहित अनुबंध के बिना मुहर वाले या कम छाप वाले होने के प्रभाव की जांच करने का विकल्प नहीं चुना। उच्च न्यायालय ने केवल यह अभिनिर्धारित किया कि, जैसा कि इस मुद्दे को संदर्भित किया गया था

16 (2018) 6 एस. सी. सी. 21

17 (2018) 4 एस. सी. सी. 743

18 (1979) 3 एस. सी. सी. 745 सी

एन. एन. ग्लोबल 14 में संविधान पीठ ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

46. सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्या द्रोलिया 13 में, एक मध्यस्थता खंड पर प्रभाव के मुद्दे पर, अंतर्निहित समझौते पर मुहर नहीं लगाई गई थी या कम छाप दी गई थी, कभी भी निर्णय या घोषणा नहीं की गई थी। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में जो बाध्यकारी था, वह उसका अनुपात निर्णय था, न कि उसका आज्ञाकारी आदेश। उच्च न्यायालय ने इस याचिका की जांच करने का विकल्प नहीं चुना कि मध्यस्थता समझौता अप्रवर्तनीय था, क्योंकि यह एक अप्रकाशित/अल्पमुद्रित दस्तावेज में निहित था, उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में एक आज्ञाकारी उक्ति का निष्कर्ष, बाध्यकारी नहीं था, जैसा कि कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9 में स्पष्ट रूप से बताया गया था इस संदर्भ में कि क्या, इस बिंदु पर, विद्या द्रोलिया 13 में निर्णय करियर

में एसएलपी की सुनवाई करने वाली पीठ पर एक बाध्यकारी मिसाल थी **इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9.कैरियर संस्थान में निर्णय** इसलिए, एजुकेशनल सोसाइटी 9 को इस मुद्दे पर सीधे एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में एक आज्ञाकारी उक्ति का अधिकारियों पर बाध्यकारी पूर्ववर्ती मूल्य है। **न्यायिक पदानुक्रम में निम्न।करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9** हालाँकि, एक निर्णय में आज्ञाकारी उक्ति की पहचान कैसे की जाए, इस पर एक अधिकार है।

47. जैसा कि करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी 9 में वकालत की गई है, व्युत्क्रम परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अलॉयज वोबेन 2 का पैरा 19, पूरी तरह से, आज्ञाकारी है, क्योंकि, भले ही पैरा 19 को निर्णय से हटा दिया जाए, लेकिन इसका निष्कर्ष अपरिवर्तित रहेगा।

48. सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) के अनुपात के पूर्ववर्ती मूल्य की एक विस्तृत परीक्षा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में निर्णय और आज्ञाकारी उक्ति थी **निपटान निदेशक बनाम एम. आर. अप्पाराव 19 में किया गया।द.** कानून का निम्नलिखित कथन, रिपोर्ट के पैरा 7 में, इस मुद्दे पर कानून को स्पष्ट करता है:

7. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।उपरोक्त अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को कानून घोषित करने का अधिकार देता है।अतः यह न्यायालय का एक अनिवार्य कार्य है कि - एक कानून की व्याख्या करें।तथ्यों जैसे कानून के अलावा अन्य मामलों पर न्यायालय के बयानों का कोई बाध्यकारी बल नहीं हो सकता है क्योंकि दो मामलों के तथ्य समान नहीं हो सकते हैं।लेकिन जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात

है न कि तथ्यों का कोई निष्कर्ष। न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के आलोक में, समग्र रूप से किसी निर्णय को पढ़ने पर पाया जाने वाला सिद्धांत ही अनुपात बनाता है, न कि कोई विशेष शब्द या वाक्य। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी निर्णय ने-कानून घोषित किया है-इसे कानून नहीं कहा जा सकता है जब एक बिंदु है रियायत पर निपटाया जाता है और जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है। न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उस मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुए थे जिसमें निर्णय दिया गया था। न्यायालय द्वारा अपने समक्ष किसी मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर एक अवलोकन, जिसे अनुपात निर्णय से अलग करते हुए "आज्ञाकारी उक्ति" कहा जाता है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि निर्णय की आवश्यकता हो। इस तरह के आज्ञाकारी का एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि निर्णय के लिए अवलोकन अनावश्यक था, लेकिन भले ही एक आज्ञाकारी का एक पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी प्रभाव न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए, जो कानून अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी होगा, वह किसी दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा उठाए गए और तय किए गए बिंदुओं की सभी टिप्पणियों पर लागू होगा।।

(जोर दिया गया)

अतः उच्चतम न्यायालय ने निदेशक के पैरा 7 में कहा है - बस्तियाँ¹⁹ ने अभिनिर्धारित किया कि

((i) तथ्यों जैसे कानून के अलावा अन्य मामलों पर न्यायालय के बयानों का कोई बाध्यकारी बल नहीं है।

((ii) यह एक निर्णय का अनुपात है जो तथ्य के निष्कर्षों को नहीं, बल्कि उसे बांधता है।

((ग) निर्णय के अनुपात को न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के आलोक में समग्र रूप से निर्णय को पढ़ने पर प्राप्त किया जाना चाहिए, और किसी विशेष शब्द या वाक्य पर भरोसा करके इसका आकलन नहीं किया जा सकता है।

((iv) जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है, (v) न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुए थे।

(vi) एक आज्ञाकारी उक्ति, जैसा कि अनुपात निर्णय से अलग है, अदालत द्वारा उसके समक्ष एक मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर एक अवलोकन है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि निर्णय की आवश्यकता हो,

(vii) जैसा कि एक आज्ञाकारी उक्ति घोषित निर्णय के लिए अनावश्यक है, इसका बाध्यकारी पूर्ववर्ती मूल्य नहीं हो सकता है,

(viii) भले ही आज्ञाकारी का बाध्यकारी पूर्ववर्ती मूल्य न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका काफी महत्व है और (ix) अनुच्छेद 141 के तहत बाध्य करने वाला कानून किसी दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा उठाए गए और तय किए गए बिंदुओं पर सभी टिप्पणियों पर लागू होगा।

49. अधिकारियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आज्ञाकारी आदेश के पूर्ववर्ती मूल्य के बारे में न्यायिक राय में काफी तरलता है। न्यायिक पदानुक्रम में निम्न। अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राज्य मध्य प्रदेश 20, उच्चतम न्यायालय इस प्रकार टिप्पणी करता है:

—24.इस स्तर पर, न्यायालय के आदेश में केवल अवलोकन या आज्ञाकारी कथन की प्रकृति और दायरे पर विचार करना उचित है। अभिव्यक्ति-ओबिटर डिक्टा या-डिक्टा की चर्चा अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस 2डी, वॉल्यूम में की गई है। 20, पी।437 इस प्रकार:

—74.डिक्टा

आम तौर पर, एक अदालत केवल प्रस्तुत किए गए विशेष मामले को निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रश्नों का निर्णय करेगी। लेकिन एक बार जब कोई अदालत अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर लेती है, तो उसके निर्णय के लिए सभी भौतिक प्रश्न खुले होते हैं; वह इस तरह से शामिल सभी प्रश्नों का उचित निर्णय ले सकती है, भले ही यह आत्यन्तिक रूपिणाम के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी का निर्णय लिया जाना चाहिए। उदाहरण के मुकदमा, यह किसी अधिनियम की संवैधानिकता के प्रश्न का निर्धारण कर सकता है, हालांकि मामले के निपटारे के मुकदमा यह आत्यन्तिक रूप आवश्यक नहीं है, यदि संवैधानिकता का मुद्दा मुकदमे में शामिल है और इसका निपटान सार्वजनिक महत्व का है। एक राय में एक अभिव्यक्ति जो अदालत द्वारा किए गए निर्णय का समर्थन करने के लिए आवश्यक नहीं है, वह डिक्टम या ओबिटर डिक्टम है।

डिक्टम 'या' ओबिटर डिक्टम 'अदालत के निर्णय लिया से अलग है कि तथाकथित' मामले का कानून 'केवल डिक्टा तक नहीं फैला है, और केवल डिक्टा टकटकी निर्णय लिया के सिद्धांत के तहत बाध्यकारी नहीं है।

जैसा कि किसी विशेष राय पर लागू होता है, यह सवाल कि उसका कोई निश्चित हिस्सा केवल एक उक्ति है या नहीं, कभी-कभी तर्क का विषय

होता है। और जबकि 'डिक्टम' और 'ओबिटर डिक्टम' शब्दों का उपयोग आम तौर पर एक राय में अभिव्यक्तियों के संबंध में किया जाता है जो निर्णय लिया का समर्थन करने के लिए आवश्यक नहीं हैं, स्टेर डिसिसिस के सिद्धांत के संबंध में, केवल ओबिटर और 'न्यायिक डिक्टा' के बीच एक अंतर निकाला गया है, बाद वाला अदालत द्वारा जानबूझकर पारित एक बिंदु पर राय की अभिव्यक्ति है॥

(जोर दिया गया)

आगे पृष्ठ 525 और 526 पर, उक्ति के प्रभाव पर चर्चा की गई है:—190.कानूनी बिंदु पर निर्णय; उक्ति का प्रभाव

... टकटकी निर्णय लिया के सिद्धांत को लागू करने में, एक पकड़ और एक उक्ति के बीच एक अंतर किया जाता है। आम तौर पर टकटकी लगाने का निर्णय लिया अदालत की राय के ऐसे हिस्सों से नहीं जुड़ा होता है जो केवल निर्देश होते हैं। एक कथन को किसी अभिनिर्णय से अलग करने का कारण यह कहा गया है कि अदालत के समक्ष वास्तव में एक प्रश्न और उसके द्वारा तय किए गए प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और उस पर पूरी तरह से विचार किया जाता है, जबकि अन्य सिद्धांतों पर, हालांकि निर्णय किए गए मामले के संबंध में विचार किया जाता है, शायद ही कभी अन्य मामलों पर उनके संभावित प्रभाव के रूप में पूरी तरह से जांच की जाती है। फिर भी अदालतों ने कभी-कभी डिक्टा को होल्डिंग्स के समान प्रभाव दिया है, विशेष रूप से जहां 'ओबिटर डिक्टा' से अलग 'न्यायिक डिक्टा' शामिल हैं॥

25. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन के अनुसार

(3आर. डी. एडन., 2005), अभिव्यक्ति-अवलोकन का अर्थ है

एक-दृष्टिकोण, प्रतिबिंब; टिप्पणी; बयान; सत्य या तथ्यों का अवलोकन; भाषण या लेखन में टिप्पणियाँ किसी अवलोकन के संदर्भ में।

26. व्हार्टन लॉ लेक्सिकन (14वां संस्करण, 1993) शब्द को परिभाषित करता है-आज्ञाकारी उक्ति एक राय के रूप में जो किसी निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है; एक मामले के दौरान एक न्यायाधीश द्वारा बनाई गई कानून के रूप में एक अवलोकन, लेकिन इसके निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है, और इसलिए, कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है; जिसे अक्सर आज्ञाकारी उक्ति कहा जाता है, 'वैसे एक टिप्पणी'।
27. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, (9वां संस्करण, 2009)-ओबिटर डिक्टम शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

—आज्ञाकारी उक्ति।—न्यायिक राय देते समय की गई एक न्यायिक टिप्पणी, लेकिन वह जो मामले में निर्णय के लिए अनावश्यक है और इसलिए पूर्ववर्ती नहीं है (हालांकि इसे प्रेरक माना जा सकता है)।— अक्सर संक्षिप्त में डिक्टम या, कम आम तौर पर, ओबिटर।...

—किसी न्यायाधीश द्वारा किसी कारण पर अपने निर्णय में, अर्थात् संयोग से या संपार्श्विक रूप से, और न्यायालय के समक्ष सीधे प्रश्न पर नहीं; या यह न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा केवल चित्रण, तर्क, सादृश्य या सुझाव के माध्यम से प्रतिपादित कानून का कोई भी कथन है।वकीलों के आम भाषण में, कानूनी राय की ऐसी सभी गैर-न्यायिक अभिव्यक्तियों को-डिक्टा, या-ओबिटर डिक्टा के रूप में संदर्भित किया जाता है, इन दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।॥

28. शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण, खंड। 29 अभिव्यक्ति-आज्ञाकारी डिक्टा या-डिक्टा को इस प्रकार परिभाषित करता है:

—डिक्टा एक न्यायाधीश की राय होती है जो अदालत के संकल्प या निर्धारण को मूर्त रूप नहीं देती है, और बिना किसी तर्क या मुद्दे पर पूर्ण विचार के किए गए, स्वयं न्यायाधीश के घोषित जानबूझकर किए गए निर्णय नहीं होते हैं; आज्ञाकारी निर्देश वे राय हैं जो किसी भी तरह से व्यक्त की जाती हैं, न कि लंबित बिंदु या

प्रश्न पर, जैसे कि मामले के मुख्य विषय से संपार्श्विक विषयों को समय के लिए अलग कर दिया जाता है; यह केवल एक न्यायाधीश द्वारा उसके समक्ष मामले द्वारा सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर अवलोकन है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि उसके द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो; 'आज्ञाकारी आदेश' को तर्क या चित्रण के रूप में बनाया जाता है, जो अन्य मामलों के लिए प्रासंगिक है, और जो किसी भी अर्थ में प्रबुद्ध या आश्वस्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो किसी भी अर्थ में नहीं है।

उनका उच्चारण करता है; कानून के सिद्धांतों की राय में चर्चा जो अदालत के समक्ष मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक, प्रासंगिक या आवश्यक नहीं हैं, 'आज्ञाकारी उक्ति' है॥

29. - डिक्टा की अवधारणा पर कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम में भी विचार किया गया है। 21, pp. 309-12 पर इस प्रकार:

—190.डिक्टा

ए। सामान्य तौर पर

एक उक्ति एक अदालत द्वारा व्यक्त की गई राय है, लेकिन जो मामले में आवश्यक रूप से शामिल नहीं है, एक निर्णय के बल का अभाव है; एक न्यायाधीश द्वारा एक ऐसे बिंदु पर व्यक्त की गई राय जो मामले में आवश्यक रूप से उत्पन्न नहीं होती है; एक बयान या एक राय में धारण करना जो किसी भी मुद्दे के लिए उत्तरदायी नहीं है और मामले के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है; एक ऐसी राय जिसमें न्यायिक दिमाग को पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक सटीक प्रश्न के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है; या एक न्यायाधीश की राय जो अदालत के संकल्प या निर्धारण को मूर्त रूप नहीं देती है, और बिना तर्क के, या मुद्दे पर पूर्ण विचार किए, न कि स्वयं न्यायाधीश का घोषित जानबूझकर निर्धारण। 'डिक्टम'

शब्द का उपयोग आम तौर पर 'ओबिटर डिक्टम' के संक्षेपाक्षर के रूप में किया जाता है जिसका अर्थ है एक टिप्पणी या राय जो वैसे भी बोली जाती है।

इस तरह की अभिव्यक्ति या राय, एक सामान्य नियम के रूप में, टकटकी निर्णय लिया नियम के भीतर अधिकार या मिसाल के रूप में बाध्यकारी नहीं है, यहां तक कि उस अदालत से निचली अदालतों पर भी जहां से ऐसी अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई है, चाहे उसे कितनी भी बार दोहराया जाए। यह सामान्य नियम विशेष रूप से लागू होता है जहां कथन के विपरीत पूर्व निर्णय होते हैं जिन्हें उक्ति माना जाता है; जहां बयान को फिर से सुनने पर उक्ति घोषित किया जाता है; जहां उक्ति एक ऐसे प्रश्न पर होती है जिसे अदालत स्पष्ट रूप से बताती है कि वह तय नहीं करती है; या जहां यह अधिनियम के विपरीत है और एक असमान परिणाम उत्पन्न करेगा। यह भी माना गया है कि एक उक्ति 'मामले का कानून' नहीं है, न ही न्यायपालिका है॥

30. डिक्टा की अवधारणा की चर्चा हेल्सबरी के लॉज ऑफ़ इंग्लैंड, 4थ एडन में की गई है। (पुनर्मुद्रण), खंड। 26, पैरा 574 इस प्रकार है:—

574. डिक्टा।—बयान जो निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं, जो अवसर से परे जाते हैं और एक नियम निर्धारित करते हैं कि यह हाथ में उद्देश्य के लिए अनावश्यक है, वे हैं CS (COMM)

सामान्यतः 'डिक्टा' कहल जाइत अछि। उनके पास किसी अन्य अदालत पर कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है, हालाँकि उनकी कुछ प्रेरक प्रभावकारिता हो सकती है। एक न्यायाधीश की केवल पारित टिप्पणियों को 'आज्ञाकारी आदेश' के रूप में जाना जाता है, जबकि निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होने वाले बिंदु पर न्यायाधीश की राय के प्रतिपादन पर विचार किया जाता है, और इसलिए अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं माना जाता है, जिसे 'न्यायिक आदेश' कहा जाता है। एक तीसरे प्रकार के उक्ति में एक

न्यायाधीश के बयान में शामिल हो सकता है कि अन्य मामलों में क्या किया गया है जो रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

... अभ्यास टिप्पणियाँ, बिना तर्क के दिए गए निर्देश होने के कारण, बाध्यकारी न्यायिक प्रभाव नहीं रखते हैं। तर्क के दौरान अदालत के सदस्यों द्वारा अंतर्वर्ती टिप्पणियाँ, जबकि प्रेरक वजन की होती हैं, न्यायिक घोषणाएं नहीं होती हैं और कुछ भी तय नहीं करती हैं॥

31. एम. सी. डी. बनाम वर्णम कौर 21, और कर्नाटक एस. आर. टी. सी. बनाम.

महादेव शेटी 22, इस न्यायालय ने कहा है:—

12.... केवल आकस्मिक भावों का कोई महत्व नहीं होता है। एक न्यायाधीश की हर पारित अभिव्यक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, को एक पूर्व कैथेड्रल बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसमें अधिकार का भार होता है॥

32. हरियाणा राज्य बनाम रणबीर 23 के मामले में इस न्यायालय ने चर्चा की है।

ओबिटर डिक्टम की अवधारणा इस प्रकार है:—

13.... एक निर्णय, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, एक प्राधिकरण है कि वह क्या तय करता है और न कि उससे तार्किक रूप से क्या निकाला जा सकता है। डिक्टा और ओबिटर के बीच का अंतर सर्वविदित है। ओबिटर डिक्टा कमोबेश निर्णय के लिए अनावश्यक है। यह एक दृष्टिकोण या भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है। देखें। **ए. डी. एम., जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 24.** यह भी ठीक है। यह तय किया गया कि जो कथन अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं हैं, वे आज्ञाकारी हैं और आधिकारिक नहीं हैं।

33. गिरनार व्यापारी बनाम महाराष्ट्र राज्य 25 में यह न्यायालय आयोजित किया गया है:—

53.... इस प्रकार, न्यायालय की टिप्पणियाँ मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी प्रश्न से संबंधित नहीं थीं और तदनुसार, इसे अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अच्छी तरह से तय किया है कि केवल अनुपात

-
- 21 (1989) 1 एससीसी 101**
22 (2003) 7 एससीसी 197
23 (2006) 5 एससीसी 167
24 (1976) 2 एससीसी 521
25 (2007) 7 एससीसी 555

निर्णय एक बाध्यकारी या आधिकारिक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है, यह स्पष्ट है कि केवल सामान्य टिप्पणियों या अदालत की आकस्मिक अभिव्यक्तियों पर रखी गई निर्भरता, उत्तरदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है॥

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आज्ञाकारी उक्ति अदालत द्वारा उसके समक्ष वास्तविक मुद्दे का निर्णय लेते समय केवल एक अवलोकन या टिप्पणी है। केवल आकस्मिक कथन या अवलोकन जो हाथ में मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक, प्रासंगिक या आवश्यक नहीं है, न्यायालय के फैसले का हिस्सा नहीं है और इसका कोई आधिकारिक मूल्य नहीं है। न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचार या राय की अभिव्यक्ति केवल एक अनौपचारिक टिप्पणी है जो न्यायालय के समक्ष लंबित वास्तविक मुद्दों का जवाब देने से विचलित होती है। इन अनौपचारिक टिप्पणियों को निर्णय के आधिकारिक या कार्यात्मक भाग के दायरे से परे माना या माना जाता है॥

50. स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनाम यू. ओ. आई. 26 में उच्चतम न्यायालय ने ओबिटर के मुद्दे पर इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

—52. श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों में से एक यह है कि उपरोक्त पैराग्राफ में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां कि लॉटरी एक कार्रवाई योग्य दावा है, एक आज्ञाकारी उक्ति पर आधारित है क्योंकि प्रश्न विचार के लिए नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अदालत को इस बात पर विचार करना था कि क्या लॉटरी टिकट तमिलनाडु सामान्य बिक्री अधिनियम, 1959 की खंड 2 (जे) के अर्थ के भीतर वस्तु हैं या नहीं, जैसा कि संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 9 में संविधान पीठ द्वारा देखी गई खंड 2 (जे) में वस्तुओं की परिभाषा में कहा गया है कि-वस्तुओं का अर्थ है सभी प्रकार की चल संपत्ति (समाचार पत्र, कार्रवाई योग्य दावों, स्टॉक, शेयरों और प्रतिभूतियों के अलावा)। परिभाषा में उल्लिखित माल से कार्रवाई योग्य दावों का बहिष्कार भी परिभाषा का एक हिस्सा है। यदि कोई विशेष वस्तु बहिष्करण द्वारा कवर की जाती है तो यह स्पष्ट है कि यह माल की परिभाषा में नहीं आती है। जब संविधान पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लॉटरी एक कार्रवाई योग्य दावा है तो वह खंड 2 (जे) की परिभाषा पर ही विचार कर रही थी और संविधान पीठ द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है उसे आज्ञाकारी आदेश नहीं माना जा सकता है।

53. एम. सी. डी. बनाम वर्णम कौर 21 में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 10 और 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की: (एस. सी. सी. पीपी. 109-10)

—10.... एक न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज जो बाद के न्यायाधीश पर एक प्राधिकरण के रूप में बाध्यकारी है, वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया गया था। बयान जो अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें आज्ञाकारी आदेश के रूप में अलग किया जाता है और वे आधिकारिक नहीं होते हैं।...

11. कानून की घोषणाएं, जो अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें आज्ञाकारी आदेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और आधिकारिक नहीं होते हैं॥

54. यह नहीं कहा जा सकता है कि सनराइज के फैसले में यह सवाल नहीं उठा था कि क्या लॉटरी माल है या कार्रवाई योग्य दावा है। **एसोसिएट्स बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 27.जब किसी वस्तु को ढक दिया गया था** बहिष्कृत श्रेणी द्वारा, उक्त निष्कर्ष परिभाषा और अपवर्जन खंड पर विचार करने के बाद ही उत्पन्न किया जा सकता था। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि लॉटरी को कार्रवाई योग्य दावे के रूप में रखने वाली संविधान पीठ की टिप्पणियां केवल आज्ञाकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। सनराइज एसोसिएट्स 27 में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉटरी उचित विचार के बाद कार्रवाई योग्य दावा है जो निर्णय का अनुपात है। जब 2017 के अधिनियम की खंड 2 (52) ने कार्रवाई योग्य दावे को भी शामिल करके वस्तुओं की परिभाषा का विस्तार किया, तो खंड 2 (52) में उक्त परिभाषा सनराइज एसोसिएट्स 27 में संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप है और खंड 2 (52) में होने वाली वस्तुओं की परिभाषा में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है॥

51. इसलिए, दो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इस मुद्दे का निर्धारण किया जा सकता है कि क्या निर्णय में एक मार्ग, आज्ञाकारी कथन है या अनुपात निर्णय है। एक यह जांच करना है कि क्या विचाराधीन अवलोकन और निष्कर्ष एल. आई. एस. के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, जो, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, एक प्रासंगिक विचार के रूप में, इस सवाल को भी ध्यान में रखेगा कि क्या निष्कर्ष किसी आग्रह किए गए और तर्क दिए गए मुद्दे पर वापस किया गया है, या एक तरफ एक अवलोकन है। दूसरा

व्युत्क्रम परीक्षण को लागू करके है; यदि मामले में निष्कर्ष अपरिवर्तित रहेगा, भले ही प्रश्न में मार्ग को उससे हटा दिया जाए, तो यह आज्ञाकारी है; अन्यथा, यह अनुपात है।

52. किसी भी तरह से देखे जाने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री आनंद अपने इस कथन में सही हैं कि एलॉयस वोबेन 2 का पैरा 19 वास्तव में आज्ञाकारी है।

53. विवाद में मुद्दा, अलॉयस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वोबेन 2, यह था कि क्या एनरकॉन एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित उल्लंघन मुकदमों में जवाबी दावे कर सकता है, जिसमें एलॉयस वोबेन के उन्हीं पेटेंट को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके लिए पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत रद्द करने की याचिकाएं पहले से ही उनके द्वारा दायर की गई थीं। उस मुद्दे को अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी. पी. सी. की खंड 10 के साथ स्थिति की तुलना करके तय किया गया था, इस प्रकार, निर्णय के पैरा 25 से 27.3 में इस प्रकार:

—25.ए-सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए प्रतिदावे को उस व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमे के मुकदमा में समझा जाना चाहिए जिसे प्रतिवादी के मुकदमा में शामिल किया गया है।ए-प्रतिवाद अनिवार्य मुकदमा से एक मुकदमे में उठाए गए दावे को बाधित करने के लिए दायर किया जाता है।ए-प्रतिदावे की सुनवाई अभियोक्ता द्वारा दायर मुकदमे के साथ संयुक्त मुकदमा से की जाती है, और इसका प्रभाव प्रतिदावे के समान होता है।इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ए-काउंटरक्लेम को एक वाद के रूप में माना जाता है, और यह अभियोगों पर लागू नियमों द्वारा शासित होता है।मुकदमे की सुनवाई मुकदमाने वाली अदालत को, साथ ही-साथ-प्रतिवाद को, मुकदमे में की गई प्रार्थनाओं और प्रतिवाद में की गई प्रार्थनाओं पर भी अपना निर्णय सुनाना होता है।चूंकि ए-काउंटरक्लेम एक स्वतंत्र मुकदमे की प्रकृति का है, ए-काउंटरक्लेम को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां प्रतिअभियोक्ता ने पहले ही अभियोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, उसी वाद हेतुक कारण पर।उपरोक्त निष्कर्ष

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद-सी. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की खंड 10 में खंड 151 सी. पी. सी. के साथ पठित कानून के स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है। उपरोक्त दोनों प्रावधानों को नीचे निकाला जा रहा है:

—10.मुकदमा में रहें।—कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण के साथ आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें मुद्दा भी उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व में स्थापित वाद में प्रत्यक्ष मुकदमा से और पर्याप्त मुकदमा से जारी है, या उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी उसी शीर्षक के तहत वाद करने का दावा करता है जहां ऐसा वाद उसी में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में लंबित है, जिसे दावा की गई राहत देने की अधिकार क्षेत्र है, या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या जारी भारत की सीमाओं से परे किसी भी न्यायालय में और जिसकी समान अधिकार क्षेत्र है, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

स्पष्टीकरण।—विदेशी अदालत में एक मुकदमे की विचाराधीनताता भारत में अदालतों को वाद हेतुक एक ही कारण पर आधारित मुकदमे की सुनवाई मुकदमाने से नहीं रोकती है।

151. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना।—इस संहिता की किसी भी बात को ऐसे आदेश देने की अदालत की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) 101/2022 44 का पृष्ठ 36 हो।

न्यायाधीश के उद्देश्यों के लिए या न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक॥

इसमुकदमा, जहां कोई मुद्दा पहले से ही उसी पक्षकारों के बीच न्यायालय में निर्णय के मुकदमा लंबित है, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, उसी पक्षकारों के बीच उसी मुद्दे पर बाद में स्थापित मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।वर्तमान

विवाद में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एक समान प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि उत्तरदाताओं ने अपनी क्षमता में-किसी भी इच्छुक व्यक्ति के रूप में, उल्लंघन के मुकदमे की संस्था के समक्ष-निरसन याचिका दायर की थी, तो उन्हें वाद हेतुक उसी कारण पर-प्रतिवाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त स्थिति में स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि पेटेंट के अनुदान की वैधता-निरसन याचिका में निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए, उपरोक्त स्थिति में, जबकि-निरसन याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति देनी होगी,-प्रतिवाद को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, उपरोक्त स्थिति में, यह स्पष्ट है कि स्थिति को उसी तरीके से हल किया जाएगा जैसे कि प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा विभिन्न क्षेत्राधिकार अदालतों के समक्ष दायर किए गए मुकदमों में हल किया गया होगा। हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त निष्कर्ष पेटेंट अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के लिए अनिवार्य है।

26. जिन मामलों में-उल्लंघन का मुकदमा (ओं) यहाँ अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था/किया गया था (उल्लंघन के मुकदमे में अभियोक्ता के रूप में), प्रत्यर्थियों द्वारा रद्द करने की याचिका (ओं) दायर किए जाने से पहले (उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादियों के रूप में), प्रत्यर्थियों को पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) से उत्पन्न शक्ति और अधिकार के तहत पेटेंट को रद्द करने की मांग करने के लिए-प्रतिवाद (ओं) दायर करने का अधिकार था। जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, उसी सादृश्य पर-उल्लंघन मुकदमे (ओं) के जवाब में एक बार-जवाबी दावा दायर करने के बाद, यह उत्तरदाताओं के लिए खुला नहीं होगा (उल्लंघन मुकदमे में प्रतिअभियोक्ता)-निरसन याचिका (ओं) दायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें इसी तरह न्यायपालिका के नियम द्वारा वर्जित किया जाएगा। इस प्रकार, उल्लंघन मुकदमे की संस्था की तुलना में बाद में दायर की गई रद्द करने की याचिकाएं कानून में अस्थिर होंगी। ऐसे

मामलों में, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर प्रतिदावे का निपटान करते समय पेटेंट को रद्द करने की प्रार्थना पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त स्थिति में, जबकि-प्रतिवाद को आगे बढ़ाने की अनुमति देनी होगी,- निरसन याचिका को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

27. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के हाथों दी गई चार दलीलों (तत्काल निर्णय के पैरा 10 में चित्रित) और पांचवें विवाद (हमारे तत्काल निर्धारण के पैरा 22 में देखा गया) की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निष्कर्ष उससे निकलते हैं:

27.1. सबसे पहले, यदि किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत कार्यवाही दायर की है, तो यह सभी सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.)

पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत एक ही व्यक्ति को समान अधिद्वारा उपलब्ध हैं। इसमें [पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत] रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति की क्षमता में रद्द करने की याचिका दायर करने द्वारा अधिद्वारा शामिल होगा, साथ ही, [पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत भी] प्रतिवादियों की क्षमता में पेटेंट को रद्द करने की मांग करने द्वारा अधिद्वारा भी शामिल होगा।

27.2. दूसरा, यदि पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत उसमें निहित स्वतंत्रता का प्रयोग करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके खिलाफ उल्लंघन का मुकदमा दायर करने से पहले रद्द करने की याचिका दायर की जाती है, तो वह कानून में पेटेंट को रद्द करने की मांग करने से वंचित हो जाएगा (जिसके आधार पर उसके खिलाफ उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया है)। पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत प्रतिदावे के माध्यम से उन्हें दिए गए उपचार का यह इनकार, उपरोक्त पैरा 25 में वर्णित कानून के सिद्धांत पर आधारित है।

27.3. तीसरा, जहां एक-उल्लंघन मुकदमे के जवाब में, प्रतिवादी ने पहले से ही एक-प्रतिवाद द्वारा से एक पेटेंट को रद्द करने की मांग की है (जिसके आधार पर-उल्लंघन मुकदमा दायर किया गया है), प्रतिवादी इसके बाद अपनी क्षमता में-किसी भी इच्छुक व्यक्ति के रूप में संबंधित

पेटेंट पर हमला नहीं कर सकता है, एक-निरसन याचिका द्वारा से।पेटेंट अधिनियम की खंड 64 (1) के तहत एक निरसन याचिका के माध्यम से उन्हें दिए गए उपचार से इनकार भी उपरोक्त पैरा 25 में व्यक्त कानून के उसी सिद्धांत पर आधारित है।।

54. उल्लंघन के मुकदमों को स्थापित करने के लिए एलॉयस वोबेन के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था। न ही, फैसले को पढ़ने से, ऐसा प्रतीत होता है कि एनरकॉन ने कभी भी एलॉयस वोबेन द्वारा स्थापित मुकदमों की स्थिरता पर सवाल उठाया, इस आधार पर कि पेटेंट का अधिकार मुकदमे की स्थापना की तारीख को स्पष्ट नहीं हुआ था। निर्णय का पैरा 19 जिस मुद्दे से संबंधित है, अर्थात्, क्या, यदि पेटेंट के अनुदान के एक वर्ष के भीतर कोई पोस्ट ग्रांट विरोध स्थापित किया जाता है, या, उस मामले के लिए, यदि उक्त अवधि की समाप्ति तक ऐसा कोई पोस्ट ग्रांट विरोध नहीं किया जाता है, तो पेटेंटी को फिर भी एक वर्ष की समाप्ति तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है या, जहां पोस्ट ग्रांट विरोध को प्राथमिकता दी जाती है, उसकी समाप्ति तक, अलॉयज़ वोबेन 2 अन्य बातों के साथ साथ विचार के लिए कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण से कि उस मामले अन्य बातों के साथ साथ खंड 25 (2) के तहत कोई पोस्ट ग्रांट विरोध कभी नहीं किया गया था।

विशेष रूप से इन मुद्दों से निपटना, इसलिए, जैसा कि श्री आनंद ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, आज्ञाकारी है, और इसे इसका हिस्सा नहीं माना जा सकता है **एलॉयज वोबेन 2 का अनुपात निर्णय।**

55. यदि, इसलिए, किसी को एलॉयस वोबेन 2, पैरा 19 के मुख्य भाग से हटा दिया जाता है, तो मामले में निष्कर्ष वही रहेगा। व्युत्क्रम परीक्षण को भी लागू करना, इसलिए, यह स्पष्ट है कि पैरा 19 है

ओबिटर।

56. वास्तव में, यदि एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 को यह अभिनिर्धारित करने के मुकदमा में माना जाता कि जब कोई प्रतिसंहरण याचिका या अनुदान के बाद का विरोध लंबित है तो उल्लंघन का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, तो वे मुकदमे, जिनसे उस मामले में विवाद उत्पन्न हुआ था, स्वयं अक्षम होते। बल्कि, सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों पर मुकदमा चलाने के लिए एलॉयस वोबेन के अधिकार को बरकरार रखा, और एनरकॉन के प्रति-दावों को सक्षम नहीं पाया, क्योंकि एनरकॉन द्वारा पसंद की गई निरसन याचिकाएं पहले से ही लागू थीं और लंबित थीं।

57. उस ने कहा, उच्चतम न्यायालय की सभी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष, चाहे वे अनुपात में हों या आज्ञाकारी, सभी न्यायिक और पदानुक्रम में निचले स्तर के अन्य अधिकारियों द्वारा बहुत सम्मान के हकदार हैं, और आज्ञाकारी के रूप में ऐसे किसी भी निष्कर्ष की अवहेलना करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 के अपमान से कम नहीं होगा।

58. तो फिर, एलॉयस वोबेन 2 का पैरा 19 क्या कहता है?

59. एलॉयस वोबेन 2 में, सर्वोच्च न्यायालय एक लंबित मुकदमे पर एक निरसन याचिका दायर मुकदमाने के प्रभाव से चिंतित नहीं था, अनुदान के बाद के विरोध से बहुत कम।

पैरा 19, जो CS (COMM) एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में कानून की स्पष्ट घोषणा इस प्रभाव के मुकदमा पाई जाएगी कि यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर पेटेंट के खिलाफ पोस्ट ग्रांट विरोध लंबित है तो उल्लंघन का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इतना ही कहा है कि इस तरह का मुकदमा दायर किए जाने की संभावना नहीं है, और शायद असंभव है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक न्यायिक मिसाल केवल एक प्राधिकरण है जो वह लेता है, न कि उसके लिए जो तार्किक रूप से उससे प्रवाहित हो सकता है। इस मुकदमा, किसी न्यायालय के

मुकदमा एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में इस आशय के कानून के किसी भी कथन को पढ़ना संभव नहीं हो सकता है कि एक पेटेंटी, जिसे पेटेंट दिया गया है और पेटेंट का उल्लंघन किया जा रहा है, उसे पीछे बैठना चाहिए और उल्लंघन को बर्दाश्त करना चाहिए, जो एक निषेधाज्ञा मुकदमा स्थापित करने के मुकदमा शक्तिहीन है।

60. इसके अलावा, ध्यान से पढ़े जाने पर, यह देखा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने, अलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 में भी, अनुदान के बीच अंतर किया है। पेटेंट रखने के अधिकार का पेटेंट और क्रिस्टलीकरण। यह बात साफ है। निम्नलिखित वाक्यों से, उक्त पैराग्राफ में, जिन्हें स्पष्टता के लिए यहां दोहराया जा रहा है:

—नियंत्रक का निर्णय प्रकाशन की ओर ले जाता है

अनुदान (पेटेंट का)। यह प्रक्रिया पेटेंट के अनुदान के निर्णय को अंतिम रूप देती है। फिर भी, यह अंततः पेटेंट धारक के अधिकार को स्पष्ट नहीं करता है। यदि और कब, पेटेंट के अनुदान के बारे में उठाई गई चुनौतियों का पेटेंट धारक के लाभ के लिए अनुकूल रूप से निपटारा किया जाता है, तो पेटेंट रखने का अधिकार तब और फिर ही स्पष्ट हो सकता है।”

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से एक पेटेंट के अनुदान को पेटेंट रखने के अधिकार के क्रिस्टलीकरण से अलग करता है। यह अंतर, वास्तव में, श्री खेड़ा की उनके खिलाफ आपत्ति को प्रभावी ढंग से तय करता है, क्योंकि पेटेंट अधिनियम की खंड 48 के तहत पेटेंट प्राप्तकर्ताओं के अधिकार हैं -

इस अधिनियम के तहत दिए गए पेटेंट के संबंध में परिकल्पना की गई है। जहाँ तक अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ अपने पेटेंट की रक्षा करने के अधिकार की बात है, उल्लंघन के लिए मुकदमा करना, इसलिए, पेटेंट का अनुदान है। एलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 के अनुसार भी, कलेक्टर के निर्णय के परिणामस्वरूप, पेटेंट के पक्ष में पेटेंट के अनुदान का प्रकाशन होते ही ऐसा होता है।

61. इस तथ्य के अलावा कि एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में यह नहीं कहा गया है कि एक पेटेंटी, जिसे पेटेंट दिया गया है और पेटेंट का उल्लंघन किया जा रहा है, उसे पीछे हटना चाहिए और उल्लंघन को बर्दाश्त करना चाहिए, एक निषेधाज्ञा मुकदमा स्थापित करने के लिए शक्तिहीन, इस तरह का प्रस्ताव पेटेंट अधिनियम के खिलाफ भी होगा। पेटेंट अधिनियम की खंड 48 विशेष मुकदमा से एक पेटेंटी को तीसरे पक्ष को पेटेंट का उल्लंघन करने से रोकने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान किसी भी शर्त के अधीन नहीं किया गया है। एक पेटेंट का अनुदान, वास्तव में, एक पेटेंटी को इसके उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। जैसा कि श्री आनंद सही ढंग से इंगित करते हैं, उल्लंघन मुकदमे की स्थापना के मुकदमा एकमात्र वैधानिक प्रतिबंध यह है कि मुकदमा एक स्वीकृत पेटेंट से संबंधित होना चाहिए जो खंड 11 (ए) के प्रावधान में पाया जाता है, जो निर्धारित करता है कि उल्लंघन मुकदमा केवल एक स्वीकृत पेटेंट के खिलाफ स्थापित किया जा सकता है। इसलिए, यह परंतु भी प्रत्येक स्वीकृत पेटेंट के धारक को उल्लंघन के खिलाफ कानूनी रूप से आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान करने के वैधानिक इरादे को प्रकट करता है।

62. मैं अलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 को पढ़ने में असमर्थ हूँ।

29 48. पेटेंट प्राप्तकर्ताओं के अधिकार।- इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों और खंड 47 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के तहत दिया गया पेटेंट पेटेंट प्राप्तकर्ता को प्रदान करेगा -

(क) जहां पेटेंट का विषय एक उत्पाद है, वहां तीसरे पक्ष, जिनके पास उसकी सहमति नहीं है, को उन उद्देश्यों के लिए भारत में उस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, बिक्री

के लिए पेशकश करने, बेचने या आयात करने के कार्य से रोकने का अनन्य अधिकार है।

(ख) जहां पेटेंट की विषय वस्तु एक प्रक्रिया है, वहां तीसरे पक्ष, जिनके पास उसकी सहमति नहीं है, को उस प्रक्रिया का उपयोग करने के कार्य से रोकने का विशेष अधिकार है, और उन उद्देश्यों के लिए भारत में उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त उत्पाद का उपयोग करने, बिक्री के लिए पेशकश करने, बेचने या आयात करने के कार्य से:

छज्जू राम कानून का बयान जो इस वैधानिक अधिकार का अपमान करता है, पेटेंट प्राप्तकर्ता को प्रदान किया जाता है या वैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए एक शर्त के रूप में, पेटेंट दिए जाने के बाद एक साल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता या यदि उस अवधि के भीतर अनुदान के बाद विरोध दायर किया गया है, तो उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से पहले अनुदान के बाद के विरोध में अनुकूल निर्णय के लिए। वास्तव में, जैसा कि देखा गया था **फार्माकोसमॉस होल्डिंग 4 में समन्वय पीठ, कानून में ऐसी स्थिति** एक पेटेंटी और अपने पेटेंट का दावा करने के उसके अधिकार पर विनाशकारी परिणाम होंगे। इसके परिणामस्वरूप, अनिवार्य रूप से, एक पेटेंट का स्पष्ट और स्पष्ट उल्लंघन होगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी उल्लंघन पेटेंट के अनुदान से एक वर्ष की समाप्ति तक चुनौती से मुक्त हो जाएगा। इससे भी बदतर, यदि पेटेंट के अनुदान से एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुदान के बाद का विरोध दायर किया जाता है, तो श्री खेड़ा द्वारा अलॉयज वोल्बेन 2 के पैरा 19 पर की गई व्याख्या को स्वीकार करने से पेटेंट के उल्लंघन के खिलाफ आगे बढ़ने के किसी भी अधिकार से पेटेंटधारक को पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा, जब तक कि उसके पक्ष में अनुदान के बाद के विरोध का निर्णय नहीं हो जाता। यदि, इसलिए, पेटेंट के अनुदान के एक वर्ष के भीतर स्थापित अनुदान के बाद के विरोध पर निर्णय लेने में तीन वर्ष लग जाते हैं, तो पेटेंटी तीन वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होने तक अपने पेटेंट के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता है।

63. इस तरह का परिणाम स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क होगा, और पेटेंट प्राप्तकर्ता को उन मूल्यवान वैधानिक अधिकारों से वंचित करेगा जो उसे पेटेंट प्रदान करते हैं। वास्तव में, यह पेटेंट अधिनियम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा।

64. यह, शायद, इस स्थिति के बारे में स्पष्ट मुकदमा से सचेत था कि उच्चतम न्यायालय ने एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में भी, अपने अवलोकन को उल्लंघन के मुकदमे की स्थापना की संभावना तक सीमित कर दिया। किसी पद विचाराधीनता रहने के दौरान, उसकी अनुमति पर उच्चारण करने के बजाय, विरोध प्रदान करें। इस न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह एलोय्स वोबेन 2 के पैरा 19 में समापन वाक्य को "असंभव" शब्द के स्थान पर "अस्वीकार्य" शब्द को प्रतिस्थापित करके फिर से लिखे। दोहराने के लिए, एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 में इस कानूनी स्थिति की कोई घोषणा नहीं है कि, अनुदान के बाद की विपक्षी कार्यवाही की परिणति तक, एक पेटेंटी अपने पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है। सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय, उक्त मामले में, पेटेंट के खिलाफ दायर अनुदान के बाद के विरोध के खिलाफ मुकदमा दायर करने के पेटेंटी के अधिकार से संबंधित नहीं था, लेकिन उसी प्रतिवादी के अधिकार से संबंधित था कि वह एक साथ एक निरसन याचिका और मुकदमे में एक प्रतिवाद पर मुकदमा चलाए। दूसरा, यह मुद्दा भी कि क्या पेटेंट देने की तारीख से एक साल की समाप्ति तक उल्लंघन का मुकदमा दायर किया जा सकता है, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के मुकदमा कभी नहीं उठा और न ही निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि उस बिंदु पर कोई तर्क उठाए गए थे।

65. ऊपर मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरगी 5 में पारित आदेश से समर्थन मिलता है। तथ्यों के साथ-साथ उस मामले में पारित आदेशों को पहले ही कुछ विस्तार से बताया जा चुका है। उस मामले में भी सी. टी. आर. ने सर्गी के खिलाफ उल्लंघन की कार्यवाही शुरू की। सर्गी ने तर्क दिया कि उसने पेटेंट के खिलाफ एक पोस्ट ग्रांट विरोध दायर किया था, जिस पर सी. टी. आर. जोर दे रहा था और एलॉयस वोबेन 2 के पैरा 19 को देखते हुए, सी. टी. आर. द्वारा स्थापित मुकदमा को तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि पोस्ट ग्रांट स्थिति की कार्यवाही लंबित थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निवेदन को खारिज कर दिया और

सी. टी. आर. को अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा देने के लिए आगे बढ़े। सर्गी खण्ड पीठ के समक्ष अपनी अपील में सफल रहे, जो पूरी तरह से पोस्ट ग्रांट विपक्ष और सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) 101/2022 44 का पृष्ठ 43 विचाराधीनता होने के आधार पर थी।

प्रतिसंहरण याचिका, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विज्ञापन अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। एसएलपी में इसके खिलाफ फिर से वरीयता दी गई, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मुद्दे की जांच किए बिना, सर्गी द्वारा दायर अनुदान के बाद के विरोध के आधार पर केवल कार्यवाही करने में खण्ड पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को बहाल कर दिया गया।

66. सरगी 5 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आलोक में इस न्यायालय के मुकदमा अलॉयज वोबेन 2 के पैरा 19 को पढ़कर पेटेंट अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत स्थापित अनुदान के बाद की विखंडी कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान उल्लंघन के मुकदमे की स्थापना को प्रतिबंधित करना खतरनाक होगा।

67. जिस दृष्टिकोण से मैंने लिया है, मेरे लिए सीडीई एशिया 7 और नोवार्टिस 6 में समन्वय पीठों द्वारा पारित आदेशों की जांच करना आवश्यक नहीं है, जो प्रथमदृष्टया विचार व्यक्त करने वाले अंतर्वर्ती आदेश हैं। उक्त आदेशों में भी, हालांकि थोड़े अलग कारणों से, यह भी देखा गया है कि अलॉयज वोबेन 2 का पैरा 19 केवल इस आधार पर उल्लंघन का मुकदमा दायर करने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है कि पेटेंट अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत स्थापित विपक्ष की कार्यवाही लंबित है।

निष्कर्ष

68. इस मुकदमा, इस आवेदन में आग्रह किए गए किसी भी आधार पर आदेश VII नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज करने का कोई मामला मौजूद नहीं कहा जा सकता है।

69. तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

70. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव की याचिका पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है, क्योंकि यह आदेश VII नियम 11 के तहत नहीं आता है और किसी वाद की अस्वीकृति के योग्य नहीं हो सकता है, और तर्क के दौरान कभी भी आग्रह या चुनाव नहीं किया गया था। इस संबंध में अधिकार आरक्षित हैं जैसा कि पैरा 11 में दर्शाया गया है।

आई. ए. 1079/2023 (सी. पी. सी. के आदेश XIII A नियम 3 के तहत)

71. 1 अगस्त 2023 को फिर से अधिसूचित करें।

सी. हरि शंकर, जे.

15 मई, 2023

डीएसएन/एआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।